सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 183, नई दिल्ली । गुरुवार, 12 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा हथियार है, अपने पौरुष को जगाओ और इस आजादी का जश्न मनाओ

03 पुरातत्व विभाग में हो रहा श्रम कानूनों का उल्लघंन - बी एम एस

06 पशु कल्याण और नैतिक कृषि पद्धतियों का बढ़ता महत

08 गणेशोत्सव राष्ट्रीयता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतिक

क्या आपने दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा दिए गए नम्बर 42400400 पर किसी वाहन की शिकायत दर्ज कराई, क्या वह नम्बर कार्य करता है ?

संजय बाटला

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन विभाग में कार्यरत आईएएस विशेष परिवहन आयुक्त शहजाद आलम द्वारा जिस प्रकार के आदेश दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की जा रही है उससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि उन्हे इस पद पर आसीन रहकर दिल्ली की जनता की परेशानियों, सुरक्षा, सुविधा या समय पाबंद सार्वजनिक सवारी सेवा प्रदान करने से कोई मतलब नही है उनका ध्येय साफ और स्पष्ट है कैसे राज्य के राजस्व में इजाफा और उद्योगपतियों को फायदा करवाया जा सकता है। दिल्ली में परमिट कंडीशन के अंतर्गत अनिवार्य नियमों के खिलाफ चलने वाले वाहनों की शिकायत दर्ज करवाने के लिए जारी नम्बर की सेवाएं भी बंद करवाई हुई है। महिला सुरक्षा के प्रति सार्वजनिक सवारी सेवा वाहनों में अनिवार्य कार्य करते सीसी कैमरे, वीएलटीडी संयंत्र और पैनिक बटन के लिए अनिवार्य डाटा सेंटर भी इन्होंने शुरू होने में देर करवाई, वाहनों की जांच जो दिल्ली में दो शाखाओं बुराड़ी और झूलझूली क्षेत्र में थे उनमें

से प्राईवेट कम्पनी को निजी फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्रालय के आदेश को पूरा जांच किए / समझे या समझने की जगह वाहनों को झूलझूली क्षेत्र में वाहनों की जांच के दिशा निर्देश जारी कर दिए। अपने नीचे कार्यरत उपायुक्त के गलत ढंग से वाहन निर्माताओं/ डीलरो को परेशान कर एकांत में मिलने में मददगारी के लिए गलत सूचना फाइल में प्रस्तुत होने के बाद फाइल और तथ्यों की जांच करने की जगह फाइल को अपने टेबल पर रखवा कर कोई निर्णय नहीं लिया। दिल्ली में वाहन जांच शाखा के लिए कंप्यूटर जांच मशीन एवम् संचालन के टेंडर को खोलने और जांचने के लिए जिन दो उपायुक्त अधिकारियो को पासवर्ड (🔑) जारी की गई उनसे एफआईआर दर्ज करवा दी गई की पासवर्ड (🔑) गुम हो गई और जांच के आदेश जारी करने की जगह नए उपायुक्त अधिकारियो को पासवर्ड (🔑) जारी करने के निर्देश जारी कर दिए। इतना ही नहीं अपने कार्यकाल में स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द किए वाहनों का पूर्ण ब्योरा जनता के समक्ष पेश नही किया। अगर इनके कार्यकाल में इनके द्वारा जारी आदेशो, दिशा निर्देशों, एडवाइजरी की निष्पक्ष जांच हो तो सब कुछ सामने आ जाएगा की कैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया।

ट्विटर के माध्यम से परिवहन विशेष समाचार पत्र ने गृह मंत्री भारत सरकार और उपराज्यपाल दिल्ली से किया सवाल:- क्या दिल्ली में कार्यरत आईएएस अधिकारी शहजाद आलम को दिल्ली की जनता को परेशान और असुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है ?

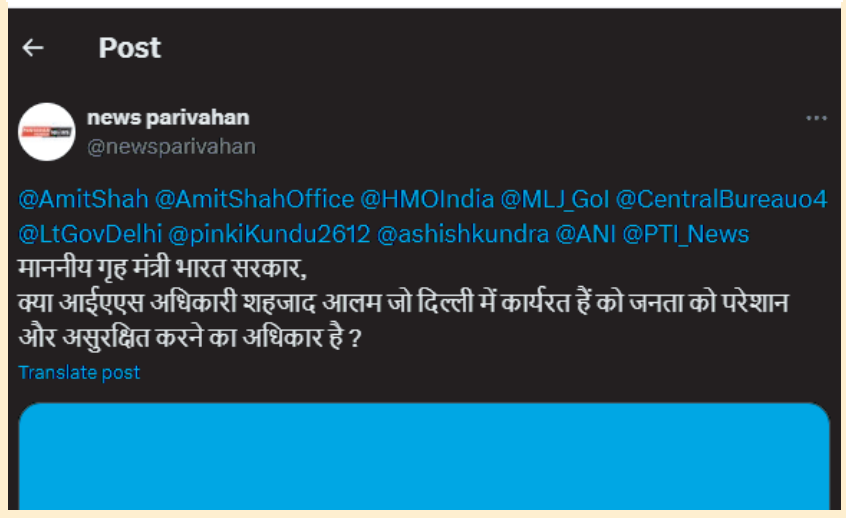

अवैध ई रिक्शों पर सख्त परिवहन विभाग, 10 दिनों में 1500 से अधिक ई-रिक्शों को JCB से किया क्रश

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में अवैध ई-रिक्शों पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने पिछले महीने से बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। अगस्त में 2000 से अधिक और सितंबर के पहले 10 दिनों में 1200 से अधिक अवैध ई-रिक्शे जब्त किए गए। इनमें से 1500 से अधिक को पहले ही नष्ट किया जा चुका है। इस कार्रवाई से अवैध ई-रिक्शा चालक सकते में हैं।

नई दिल्ली: दिल्ली में बिना नंबर प्लेट वाले अवैध ई-रिक्शों के परिचालन पर रोक लगाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने पिछले महीने से जबरदस्त मुहिम छेड़ रखी है। पूरे अगस्त में जहां 2 हजार से ज्यादा अवैध ई-रिक्शे जब्त किए गए थे, वहीं सितंबर के शुरुआती 10 दिनों में ही 1200 से ज्यादा रिक्शे जब्त किए जा चुके हैं। अवैध ई-रिक्शों को 7 दिन के अंदर ही डिसमेंटल करने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है और पिछले 10 दिनों में 1500 से ज्यादा ई-रिक्शे क्रश किए जा चुके हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग की इस मुहिम से अवैध ई-रिक्शा चलाने वालों में भी अब खलबली मच गई है।

10 दिनों में 1200 से अधिक ई-रिक्शे जब्त किए

ट्रांसपोर्ट विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 सितंबर से 10 सितंबर के बीच कुल 1290 अवैध ई-रिक्शे जब्त किए गए। इस दौरान पहले से जब्त किए गए ई-रिक्शों को डिसमेंटल करने का काम भी तेजी से चलता रहा और पिछले 10 दिनों में ही विभाग के अलग-अलग पिट पर रखे 1555 अवैध ई-रिक्शों को क्रश किया जा चुका है। इनमें से 896 ई-रिक्शे बुराड़ी पिट पर, 618 ई-रिक्शे द्वारका पिट पर और 41 ई-रिक्शे सराय काले खां पिट पर क्रश किए गए। पिछले 10 दिनों में जो ई-रिक्शे जब्त किए गए हैं, उन्हें डिसमेंटल करने का काम अब शुरू किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि बिना नंबर प्लेट वाले अवैध ई-रिक्शों को एक हफ्ते के अंदर डिसमेंटल किया जा सकता है। वहीं, किसी अन्य नियम के उल्लंघन में जब्त किए गए नंबर प्लेट वाले वैध ई-रिक्शों को अगर तीन महीने तक कोई क्लेम करने नहीं आता है, तो फिर तीन महीने बाद ऐसे रिक्शों को भी डिसमेंटल किया जा सकता है।

अगस्त में जब्त किए थे 2000 से अधिक ई-रिक्शे

इससे पहले अगस्त में कुल 2115 अवैध ई-रिक्शे जब्त किए गए थे, जबकि 1 जनवरी से 31 जुलाई 2024 के बीच केवल 665 ई-रिक्शे जब्त किए गए थे। वहीं, पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच कुल 2259 ई-रिक्शों को ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जब्त किया गया था। पिछले हफ्ते ली गई रिव्यू मीटिंग में एलजी ने भी अवैध ई-रिक्शों के खिलाफ मुहिम में तेजी लाने का निर्देश दिया था। एलजी ने ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस की जॉइंट टीमें बनाकर अवैध ई-रिक्शों के परिचालन पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया था।

प्रवर्तन शाखा आला अधिकारी और प्रवर्तन अधिकारी उपराज्यपाल की आखों में झोंक रहे हैं धूल

संजय बाटला

नई दिल्ली: उपराज्यपाल दिल्ली द्वारा दिल्ली को सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से किए गए आदेश पर कुछ नहीं कर रहा परिवहन विभाग, कर रहा है सिर्फ आखों में धूल झोंकने का काम। जी हां दिल्ली में अवैध चल रहे वाहनों खास तौर से ई रिक्शाओ को जड़ से खत्म करने की जगह नाम के लिए कुछ सड़े गले खड़े ई रिक्शाओ को बंद कर स्क्रैप कर ढिंढोरा पीट कर अपनी कमर ठुकवा और तमगा हासिल कर रहे हैं आला अधिकारी। दिल्ली की सड़कों पर आज की तारीख में कम से कम 1 लाख से अधिक ई रिक्शे बिना पंजीकरण के चालित है ओर ना जाने कितने बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं उनमें से कुछ 1000 से 2000 रिक्शा जो सड़को पर चल भी नहीं सकती जिनमे ना तो बैट्री और ना ही मोटर थी उनको बंद किया दिखा कर **दिल्ली प्रशासक उपराज्यपाल की आखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसे अधिकारी जनता की क्या सुनेगे बड़ा सवाल ?**

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

उपराज्यपाल सचिवालय के पास बस मार्शलों ने किया जोरदार प्रदर्शन

दिल्ली में उपराज्यपाल सचिवालय के पास बस मार्शलों ने दोबारा से नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. इसमें बड़ी संख्या में बस मार्शल एकजुट हुए. प्रदर्शन में बस मार्शलों ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के LG सचिवालय के पास बुधवार दोपहर बड़ी संख्या में बस मार्शल इकट्ठा हुए. इस दौरान नौकरी से हटाने का विरोध और दोबारा नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर बस मार्शलों ने प्रदर्शन किया. इन लोगों का कहना है कि इन्हें करीब 1 साल पहले नौकरी से अचानक हटा दिया गया.

दरअसल, यह लोग टेंपरेरी बेस पर नौकरी कर रहे थे. बस मार्शल के तौर पर इन लोगों की नियुक्ति की गई थी. लेकिन इन लोगों को 1 साल पहले बिना कुछ बताए हटा दिया गया, जिसके बाद इन मार्शलों की घर चलाने तक को लेकर दिक्कतें होने लगी. पहले भी बस मार्शल अपनी मांगों को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन कर चुके हैं. लेकिन आज उन्होंने बड़ा प्रदर्शन LG सचिवालय के पास किया.

इस दौरान बस मार्शल बड़ी संख्या में एकजुट हुए और नौकरी बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में बस मार्शलों ने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी आमंत्रित किया था. हालांकि, इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी से तीन विधायक शामिल हुए. बुराड़ी से विधायक संजीव झा, विधायक दिलीप पांडे और कुलदीप इस प्रदर्शन में बस मार्शल के साथ पहुंचे.

बुराड़ी विधायक संजीव झा ने कहा कि वह हमेशा से बस मार्शल की नौकरी के लिए बैठकर बात करने को तैयार हैं. वहीं, बस मार्शल का कहना है कि उनकी समस्या का समाधान आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समन्वय से ही होगा. बता दें, बस मार्शल 10 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. जिस पार्टी के पास जाते हैं, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता है, आज इसीलिए दोनों पार्टी को एक ही मंच पर आमंत्रित किया. ताकि यह लोग बैठ करके आपसी समन्वय से बस मार्शल की समस्या का समाधान कर सकें।

90 साल से अधिक जीना चाहती हैं? लंबी उम्र के ये रहे 5 रहस्य, शोध में भी हुआ खुलासा

वजन को मेंटेन रखकर आप लंबी उम्र तक जी सकते हैं. यह बात कई रिसर्च में सामने आ चुकी है. आप जीवनभर हेल्दी डाइट लें, वर्कआउट करें, मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखें तो ही आप लंबी उम्र तक जी सकती हैं. आपको ऐसी ही 5 जरूरी बातें जान लेनी चाहिए.

हेल्थलाइन के मुताबिक, अपने वजन को मेंटेन करने के लिए अगर आप सही डाइट लें, व्यायाम करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, अच्छी नींद लें और सोशल सपोर्ट हासिल करें तो आपको अपने वजन को मेंटेन रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि लंबी उम्र के पीछे आपका जीन्स, इनवायरनमेंट और कई कारकों की भी भूमिका होती है, क्योंकि वजन में बदलाव का असर भी लंबी उम्र को काफी प्रभावित करता है.

यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इस बात पर शोध किया गया कि आखिर उम्रदराज महिलाओं का उनके वजन के साथ क्या संबंध है. तो पाया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ वजन कम होना उनमें बीमारियों का कारण है. डिमेंशिया, कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस आदि. कहा है कि इस शोध में 50 हजार से अधिक महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें 56 प्रतिशत महिलाएं 90 से अधिक उम्र तक जीवित रहीं.

इस शोध में पाया गया कि जिन महिलाओं का वजन एक जैसा रह गया, उनकी उम्र 90, 95 और 100 तक रही. जबकि अगर महिला का वजन 5 किलो घटा तो उसे वजन घटने की कैटेगरी में रखा गया, 5 किलो वजन बढ़ गया तो उसे वजन बढ़ने की कैटेगरी में रखा गया, क्योंकि अगर वजन में 5 किलो के अंदर ही घटा बढ़ा तो उसे स्टेबल वेट की कैटेगरी में गिना गया. इस तरह पाया गया कि जिनका वजन एक जैसा रह गया, उनकी उम्र लंबी रही.

उम्रदराज महिलाएं अगर अपनी उम्र को लंबा बनाना चाहती हैं तो इसके लिए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है. हेल्दी डाइट का सेवन करें, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन, होल ग्रेन, हेल्दी फैट का सेवन करें, प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं. इसके अलावा फिजिकली एक्टिव रहें, ओवर ईटिंग से बचें, योग करें, हाइड्रेशन का ख्याल रखें, अच्छी नींद लें, डॉक्टर से चेकअप कराती रहें.

इस तरह अगर आप अपनी डाइट को लेकर सतर्क रहें, वर्कआउट करें, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने का प्रयास करें व स्मोकिंग या अल्कोहल से दूरी बनाएं तो आप अपने वजन को मेंटेन रख सकती हैं. अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो आप इसे मैनेज करने के तरीके अपनाएं और लोगों से मिलें जुलें. इस तरह आपकी उम्र तो बढ़ेगी ही, आप लंबी उम्र तक फिट जीवन भी व्यतीत कर सकेंगी.

30 की उम्र के बाद महिलाओं को जरूर फॉलो करना चाहिए 6 गोल्डन रूल्स, रहेंगी हेल्दी और ब्यूटीफुल

उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर टाइटनेस, ड्राइनेस, रिंकल और फाइन लाइन बनने लगती है. यही नहीं हमारी फिटनेस भी जाने लगती है. आइए जानते हैं इसका उपाय.

हर उम्र की महिलाओं का यह सपना होता है कि वह हमेशा खूबसूरत और फिट दिखें. लेकिन उम्र के लक्षण को हम रोक नहीं सकते क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है. हालांकि अगर महिला होने के नाते अगर आप अपनी सेहत पर शुरुआती दिनों से ही ध्यान दें और अच्छे तरीके से देखभाल करें तो उम्र से पहले आप एजिंग के लक्षणों को कम कर सकती हैं. यही नहीं, अगर आप 30 की उम्र से ही अपने स्किन को लेकर सचेत रहें तो यह रिंकल और फाइनलाइन की समस्या को दूर कर सकता है. यहां हम बता रहे हैं कि आप किस तरह नेचुरल तरीके से उम्र के असर को रफ्तार को कम कर सकती हैं.

30 की उम्र के बाद इन बातों का रखें ख्याल

पानी खूब पिएं

स्टडी के मुताबिक, पानी की कमी होने पर शरीर में मेटाबॉलिज्म कम होने लगता है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है और यह स्किन की इलास्टिसिटी को प्रभावित करती है. इसलिए अपने पानी के इंटेक पर नजर रखें और भरपूर पानी पिएं.

वर्कआउट करें

अगर आप 30 की उम्र के बाद भी रेगुलर वर्कआउट करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें तो यह आपकी आपके मसल्स को कमजोर नहीं होने देंगे और बॉडी व शरीर पर सुडौलता बना रहता है.

धूप से बचें

जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक, स्किन एजिंग का सबसे बड़ा कारण यूवी किरणें हैं. ऐसे में रोज एसपीएफ 30 सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें और सनग्लास का प्रयोग करें.

अल्कोहल स्मोकिंग से बचें

ये दोनों ही आदतें स्किन पर रिंकल की वजह होती हैं, यह स्किन कैंसर का कारण भी बन सकता है. ऐसे में जहां तक हो अल्कोहल और स्मोकिंग से खुद को दूर रखें.

भरपूर सोएं

30 की उम्र के बाद भरपूर सोना काफी जरूरी होता है. आप कम से कम 8 घंटे की नींद रात में जरूर पूरा करें. इसके अलावा सोने और जागने सम्पल स्लिप शेड्यूल का ध्यान रखें.

हेल्दी डाइट जरूरी

स्किन को परफेक्ट रखने के लिए आप हेल्दी डाइट का सेवन करें. इसके लिए भरपूर फल, सब्जियां, अनाज आदि खाने में शामिल करें.

इस तरह आप लंबी उम्र तक खुद को फिट रख सकेंगी और हेल्दी रहने की वजह से आपकी स्किन और बालों की समस्या भी दूर होगी.

आप भी बनना चाहती हैं इंडिपेंडेंट, महिलाएं इन 5 चीजों पर करें फोकस, इन तरीकों से बढ़ाएं पहला कदम

कई बार महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बन पाना आसान नहीं होता है. लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट वुमेन होने की ख्वाहिश रखती हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग और आत्मविश्वास जैसी चीजों पर फोकस करके आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा सकती हैं.

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का रास्ता कई बार काफी मुश्किल होता है. ऐसे में इंडिपेंडेंट बनने के लिए ज्यादातर महिलाओं को काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए किन बातों पर फोकस करना जरूरी होता है.

कई बार चाहकर भी महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम नहीं बढ़ा पाती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सी महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट होना काफी मुश्किल भरा टास्क होता है. ऐसे में अगर आप कुछ चीजों पर फोकस करते हुए आगे कदम बढ़ाती हैं, तो आत्मनिर्भर बनने का आपका रास्ता आसान हो सकता है. तो आइये जानते हैं इसके बारे में.

सेल्फ कॉन्फिडेंस होना है जरूरी

आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है. इंडिपेंडेंट बनने के लिए ये आपका पहला कदम हो सकता है. ऐसे में जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की कोशिश करें. साथ ही प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ तक के डिसीजन आप खुद पूरे विश्वास के साथ लेने का प्रयास करें. इतना ही नहीं अगर कोई फैसला गलत भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी और पर न डालकर आप खुद ही लें.

फैसले लेना सीखें

ज्यादातर घरों में महिलाएं हर छोटा बड़ा फैसला घर में किसी न किसी से पूछ कर ही लेती हैं. ऐसे में उनको फैमिली मेम्बर्स या पार्टनर पर निर्भर रहने की आदत हो जाती है. लेकिन आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि आप खुद में डिसीजन मेकिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश करें. जिससे आप जरूरत पड़ने पर खुद फैसला लेने में सक्षम रहें.

भावनात्मक रूप से मजबूत बनें

आत्मनिर्भर बनने के लिए आपका भावनात्मक रूप से मजबूत बनना भी बहुत जरूरी है. इसलिए अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर रहने की जगह अपनी केयर खुद करना सीखें. इस तरह से आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहेंगी और खुद को मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग रखने में कामयाब हो सकेंगी.

फाइनेंस मैनेज करना सीखें

बहुत सी महिलाएं जॉब करने के बाद भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहती हैं. कई ज्यादातर महिलाएं फाइनेंस से जुड़े डिसीजन बिना किसी की इजाजत के लेने में हिचकिचाने लगती हैं. क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि अपने बजट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक का हिसाब आप खुद रखें. इसलिए इंडिपेंडेंट बनने के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करना सीखें.

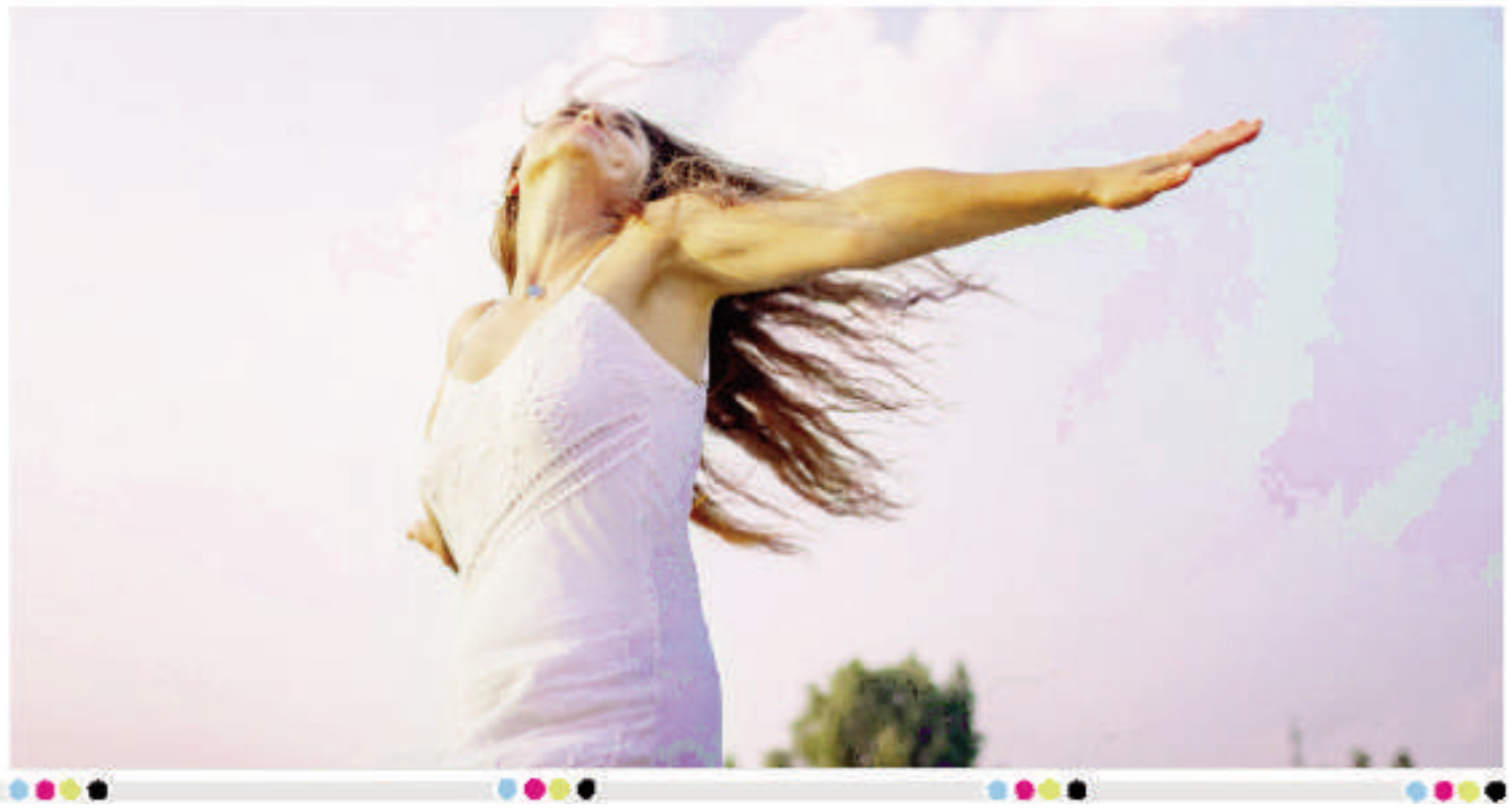

दिल्ली सरकार ने एलजी से बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने का किया आग्रह

दिल्ली सरकार ने दिल्ली के एलजी से बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने का आग्रह किया है। आतिशी ने कहा है कि निर्वाचित सरकार के रूप में हम बस मार्शलों को उनकी नौकरियों में बहाल करने के लिए हर संभव मदद और समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हालांकि सेवा विभाग एलजी के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए यह निर्णय एलजी द्वारा लिया जाना है।

नई दिल्ली। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दिल्ली के एलजी से बस मार्शलों को तुरंत बहाल करने का आग्रह किया है। आतिशी ने इस बारे में एलजी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों को नौकरी पर लगाना सेवा विभाग के अंतर्गत आता है, जो एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने निर्वाचित सरकार से इस मामले में हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया है।

आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में निर्वाचित सरकार के रूप में, हम बस मार्शलों को उनकी नौकरियों में बहाल करने के लिए हर संभव मदद और समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों की नियुक्ति की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए विभाग को कई निर्देश दिए थे।

हालांकि सेवा विभाग एलजी के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए यह निर्णय एलजी द्वारा लिया जाना है। उन्होंने कहा है कि बस मार्शलों को अचानक हटाने से वे बेरोजगार हो गए हैं, वहीं सार्वजनिक बसों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है।

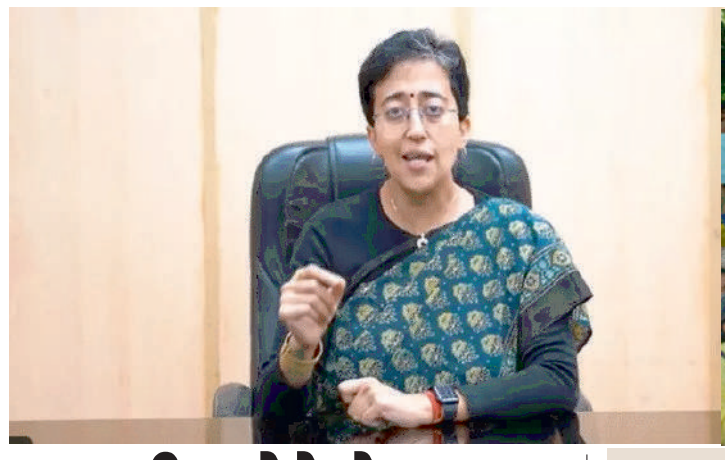

भाजपा और आम आदमी पार्टी अपने चुनावी एजेंडे के तहत झुग्गी वालों के साथ राजनीतिक खेल खेल रही है: देवेन्द्र

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में जहां एक तरफ सत्ता के लिए घमासान मचा हुआ है, वहीं दिल्ली में झुग्गीवालों के वोट बटौरने के लिए दोनो पार्टी एक से बढ़कर एक वादे और दावे कर रही है, जबकि पिछले 10 वर्शों दिल्ली की जितनी भी झुग्गियों को उजाड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की सरकारों के आदेश के द्वारा उजाड़ी गई हैं, यह किसी से छिपा नही है। विधानसभा चुनावों से पहले वोट बैंक की राजनीति करके जहां भाजपा झुग्गी बस्तियां में अपने सदस्यता अभियान के सहारे झुग्गीवालों से झूठी सहानूभूति ले रही है वहीं आम आदमी पार्टी पदयात्रा करके झुग्गियों में जाकर उन्हें एक बार फिर गुमराह कर रही है।

यादव ने कहा कि उपराज्यपाल के बारापुला नाले का निरीक्षण के बाद आप पार्टी की दिल्ली सरकार के पीडब्लूडी विभाग जहां मद्रासी कैम्प को तोड़ने के नोटिस भेजता है वहीं मनीश सिसोदिया द्वारा दल बल के साथ मद्रासी कैम्प पहुॅचकर यह बयान देना कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हम दिल्ली में झुग्गीवालों को उजड़ने नही देंगे। पूरी तरह झुग्गीवालों को धोखा देने वाला है। उन्होंने कहा कि मनीश सिसोदिया बताऐं कि यमुना किनारे चिल्ला खादर, निजामुद्दीन, शकूर बस्ती झुग्गी झौपड़ी, सराय रोहिल्ला, तुलसी नगर, दया बस्ती रेलवे लाईन के नजदीक झुग्गी, मद्रासी कैम्प, खैबर पास आदि जगहों पर झुग्गियों को उजाड़े जाने के बाद कितने लोगों को वैकल्पिक अथवा स्थाई व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की है।

यादव ने भाजपा और आम आदमी पार्टी से पूछा कि जब कोर्ट के साफ निर्देश है कि मानवता के आधार पर झुग्गियों को उजाड़ने से पूर्व उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे और पिछले वर्श संसद में पुराने कानून में संशोधन करके यह बिल पास हुआ कि 2025 तक दिल्ली की किसी भी झुग्गी को उजाड़ा नही जाऐगा। तब भाजपा और आप पार्टी की सरकारें उस पर ध्यान केन्द्रित करके झुग्गीवालों को स्थानांतरित करने की कार्यवाही क्यां नही करती? उन्होंने कहा कि कालका जी, जेलर बाग और कठपुतली कॉलोनी में झुग्गीवालों के लिए फ्लैट बनाने की योजना लाकर कांग्रेस सरकार ने काम शुरु

किया था परंतु 10 वर्शों में केन्द्र और दिल्ली सरकार इन्हें पूरा नही कर पाई, बस प्रधानमंत्री मोदी ने कालका में कुछ लोगां को चाबी देकर फोटो खिचवाई थी, परंतु अलॉटमेंट अभी तक नही की गई।

उन्होंने कहा कि यदि गरीबों, झुग्गी वालों के लिए काम करना है तो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की तरह काम करें। हमने राजीव रत्न आवास योजना के अंतर्गत दिल्ली के गरीब झुग्गीवालों के लिए 48000 हजार मकान बनाने का काम शुरु किया जिनके बनने के बाद आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्शों में एक भी फ्लैट का आवंटन नही कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गोल मार्केट, सरोजनी नगर, बापू धाम, बाराखम्बा रोड़, पंडारा रोड़ आदि जगहों की झुग्गियों को उजाड़ने से पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की थी।

उन्होंने कहा कि यह चिंताजनक है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी झुग्गीवालां को इस तर्ज पर निशाना बना रही है कि जहां भाजपा का वोट बैंक है वहां आप पार्टी कार्यवाही कर रही है और जहा आप पार्टी का वोट बैंक है वहां भाजपा झुग्गीवालों को उजाड़ने का काम रही है। मैं भाजपा और आम आदमी पार्टी से अपील करता हूॅ कि झुग्गीवाले भी दिल्ली के नागरिक है, उन्हें अपने मत का इस्तेमाल करने का स्वतंत्र अधिकार है, उनपर बदले की भावना से कार्यवाही न करें और इन मलिक बस्तियों में मौलिक और मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए काम करे ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार हो। भाजपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में झुग्गीवालों के साथ मौकापरस्ती का खेल खेलना बंद करें।

बायो डी-कंपोजर के छिड़काव के लिए अभी तक 841 किसानों ने फॉर्म भरा है- गोपाल राय

सुषमा रानी

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार इस साल भी धान की पराली गलाने के लिए खेतों में बायो डी-कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव करेगी। इसके छिड़काव से किसानों को पराली नहीं जलानी पड़ेगी, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा और खेतों की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ेगी। इस संबंध में विकास मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कृषि विभाग और पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में खेतों में पैदा किए जा रहे बासमती और गैर बासमती धान के सभी खेतों में सरकार मुफ्त में बायो डी-कंपोजर का छिड़काव किया जाएगा। इसके छिड़काव के लिए अभी तक 841 किसानों ने फॉर्म भर दिया है। सरकार इस साल 5 हजार एकड़ से ज्यादा खेतों में बायो डी-कंपोजर का छिड़काव करने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर सर्दियों के मौसम में होने वाली प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए सरकार लगातार अलग-अलग विभागों के साथ बैठक कर अपना विंटर एक्शन प्लान बनाने की तरफ बढ़ रही है। सभी विभागों को विंटर एक्शन प्लान को लेकर 21 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसके तहत पर्यावरण विभाग विंटर एक्शन प्लान की संयुक्त कार्य योजना तैयार कर रही है। इस वर्ष के 21 फोकस बिंदुओं में शामिल पराली जलाना भी सर्दियों के मौसम में प्रदूषण की समस्या को बढ़ाने में एक एहम भूमिका निभाता है। ऐसे में इस समस्या पर समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें, इसलिए हमारी सरकार ने पिछले साल की तरह इस बार भी पराली गलाने के लिए खेतों में बायो डी-कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस साल पराली गलाने के लिए 5000 एकड़ से ज्यादा खेतों में निःशुल्क बायो डी-कंपोजर का छिड़काव कराया जाएगा। अभी किसानों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। अगर जरूरत हुई तो और भी खेतों में इसका छिड़काव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूसा संस्थान बायो डी-कंपोजर दिल्ली सरकार को मुहैया करा रही है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर कुछ हिस्सों में ही धान की खेती की जाती है। दिल्ली में पराली से प्रदूषण न हो। इसके लिए सरकार ने पिछले साल बायो डी-कंपोजर का निःशुल्क छिड़काव कराया था और इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा है। इसके छिड़काव से खेतों में पराली गल गई और खेतों की उपजाऊ क्षमता में भी बढ़ोतरी देखी गई। किसानों के सामने एक समस्या यह भी रहती है कि धान की फसल की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच में समय अंतराल कम होता है। इसलिए सरकार समय रहते अभी से इसके छिड़काव की तैयारियों में जुट गई है, ताकि सारी कवायद में देरी भी न हो और किसानों को बेहतर परिणाम भी मिल सकें।

गोपाल राय ने बताया कि बायो डी-कंपोजर के छिड़काव को लेकर कृषि विभाग को किसानों से जल्द फॉर्म भरवाने के निर्देश दिए गए है। इस फार्म में किसान का डिटेल, कितने एकड़ खेत में छिड़काव करवाना चाहते हैं और फसल कटने का समय आदि का रिकॉर्ड शामिल किया जा रहा है। किसान छिड़काव की तारीख भी फार्म में दर्ज करेंगे, ताकि उसी हिसाब से उनके खेत में छिड़काव का इंतजाम किया जा सकें। अभी तक 841 किसानों ने फॉर्म भरा है। साथ ही दिल्ली के अंदर किसानो के बीच बायो डी-कंपोजर के छिड़काव को लेकर टीम द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बायो डी-कंपोजर का छिड़काव सितंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं।

"सरकार चलाने में ऐसी अस्थिरता की परिस्थितियां कभी पैदा नहीं हुई"

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता कांग्रेस ने भी 15 वर्ष संभाली थी और पूरे तीनों कार्यकाल में भाजपा विपक्ष में रही परंतु ऐसी अस्थिरता की परिस्थितियां कभी पैदा नही हुई कि विपक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई संवैधानिक सरकार पर प्रहार कर सके। यह कांग्रेस का नेतृत्व, कार्यशाली और प्रशासनिक अनुभव ही था कि आज तक कांग्रेस सरकार में रहने वाले किसी भी मंत्री या उनके विधायक ने भ्रष्टाचार और सरकारी विभागों में अनियिमितताओं के चलते अपराधिक मामले झेले हों। यादव ने कहा कि दिल्ली की जनता तक पहुॅचने और जनता की परेशानियों को समझने व उनका हल निकालने में नाकाम भाजपा और आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता की लड़ाई में सड़क पर उत्तर चुकी है।

यादव ने कहा कि अपनी साख और सरकार बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सभी मंत्री और विधायकों ने पूरी दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ है और शराब घोटालें के भ्रष्टाचार के आरोपी के रुप में जेल में बंद अरविन्द केजरीवाल के बाहर आने की आस करके पोस्टर तक निकाल रहे है केजरीवाल आऐंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को न्यायियक व्यवस्था में विश्वास रखते हुए यह नही भूलना चाहिए कि कानून अपना काम कर रहा है और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित अन्य शराब घोटाले से जुड़े लोग आरोप से बरी नही हुए हैं।

यादव ने कहा कि जिस जनता के सम्मुख आप का विधायक आपके द्वार पहुॅच रहा वह जनता आप की सरकार के भ्रष्टाचार के शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, बिजली बिलों में घोटाला, शिक्षा घोटाला, क्लास रुम घोटाला, पानी टैंकर घोटाला, गाद निकालने में घोटाला, मौहल्ला क्लीनिक घोटाला, सीवर घोटाला, एमएलए लैड राशि घोटाला, 11 विभागों की केग रिपोर्ट को रोकना, राशन घोटाला, पेन्शन घोटाला, मौहल्ला क्लीनिक घोटालों के बारे में भी आप के विधायक से पूछ रही है। यादव ने कहा कि भाजपा ने जो 10 सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे है, उन सवालों को लेकर कांग्रेस लम्बे समय से संघर्ष कर रही है, भाजपा कांग्रेस पार्टी के संघर्ष का केवल अनुसरण ही कर रही है। केजरीवाल जेल से कैसे सरकार चला रहे है, सरकारी निर्णयों का कार्यान्वन की स्थिति क्या है, छठे वित्त आयोग का गठन न होने से निगम वित्तिय रुप से पंगु बन चुका है, केग की 11 रिपोर्ट पर पब्लिक एकाउंट कमेटी की अनुशंसा की जानकारी, दिल्ली सरकार के वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज में अनुदान रोकने पर आर्थिक तंगी, अस्पतालों के ब्लॉक बनने व स्वास्थ्य क्षेत्र में करोड़ो का घोटाला, जहां झुग्गी वही मकान जैसे जनता से जुड़े मुद्दो पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के कुशासन और भ्रष्टाचारी प्रवृति के कारण जहां आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता का विश्वास उठ चुका है वहीं 15 वर्षों के निगम में लंबे भ्रष्टाचार और पिछले 10 वर्षों से जनता की अनदेखी कर रही भाजपा को 26 वर्षों से दिल्ली की जनता ने सत्ता से दूर रखा है।

"शिक्षा मंत्री ने प्रख्यात संस्थानों में नीट-जेईई की फ्री कोचिंग पा रहे छात्रों का उत्साह बढ़ाया"

सुषमा रानी

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना में छात्राओं के लिए 100 सीटें बढ़ाने का फ़ैसला लिया है। इस स्कीम का लाभ ले रहे बच्चों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा की।

बता डे कि, मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना के ज़रिए दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का डॉक्टर-इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रही है। इस स्कीम के ज़रिए हर साल कक्षा 9वीं और 11वीं के 300 बच्चों की टॉप कोचिंग संस्थानों में जेईई-नीट की फ्री कोचिंग के लिए चुना जाता है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने प्रख्यात संस्थानों में नीट-जेईई की फ्री कोचिंग पा रहे छात्रों से बातचीत की, कोचिंग के उनके अनुभवों को जाना और उनका उत्साह बढ़ाया।

इस मौक़े पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने सपने पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें; सरकार पैसों की कमी कभी भी उनके सपनों के आड़े नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि,सीएम अरविंद

केजरीवाल का विज़न है कि अमीर हो या ग़रीब हर परिवार का बच्चा आगे बढ़े अपने सपने पूरे करें इसलिए हमनें इस स्कीम की शुरुआत की।

लड़कियों की आगे बढ़ने के और मौक़े मिल सके इसे देखते हुए शिक्षा मंत्री आतिशी ने घोषणा की कि, आगे सत्र से मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना में छात्राओं के लिए 100 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जायेंगी।

कुछ छात्रों ने बताया कैसे मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना उनके सपनों को पूरा करने में मददगार बन रही है-

क्या है केजरीवाल सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना

कम्पटीशन के इस दौर में जेईई-नीट की तैयारी करने वाले दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों के लिए कोचिंग की महँगी फ़ीस बाधा न बने इसलिए साल 2022 में मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली विद्यार्थी कोचिंग योजना की शुरुआत की गई।

इस योजना के तहत कक्षा 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों का स्कीम के लिए एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है और हर साल दोनों कक्षाओं के लिए 150-150 बच्चों को चुना जाता है। इसके पश्चात सरकार अपने इनपेनल्ड कोचिंग संस्थानों से 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को 4 साल तो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को 2 साल जेईई-नीट की मुफ़्त कोचिंग दिलवाती है।

आपातकालीन प्रतिक्रिया और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र स्कूल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सरकारी (सह-शिक्षा) एसआर। एसईसी. स्कूल चरण -2, डीडीए फ्लैट्स कालका जी, नई दिल्ली -110019 स्कूल आईडीः 1925041 दिल्ली ब्रिगेड ने गवर्नमेंट (को-एड) एसआर में एक विशेष सत्र आयोजित किया। एसईसी. स्कूल चरण -2, डीडीए फ्लैट्स कालका जी, 9 को नई दिल्ली-110019 सितंबर 2024। इस सत्र का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को शिक्षित करना था हृदय और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों का प्रबंधन करना। इसमें सुरक्षा दिशानिर्देश, मान्यता और चरण-दर-चरण शामिल थे- चरणबद्ध कार्रवाई, और सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) प्रदर्शन। COVID-19 के बाद से महामारी के कारण कई व्यक्ति लंबे समय तक लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं, जिससे इसका खतरा बढ़ रहा है गंभीर हृदयाघात, विशेषकर युवा युवाओं में।

स्कूल द्वारा समर्थित, चार शिक्षकों और 555 छात्रों ने सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया प्राचार्य एवं समिति सदस्य. सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक प्रतिभागियों ने प्रश्न पूछे और डमी पर सही सीपीआर का अभ्यास किया। उन्होंने कैजुअल्टी हैंडलिंग और शिफ्टिंग, एंडिंग भी सीखी जीवंत बातचीत के साथ.

श्री पी डी वर्खिया सहायक आयुक्त के नेतृत्व में दक्षिण-पूर्व और दक्षिण जिलों की दिल्ली ब्रिगेड टीम। सत्र का संचालन दल अधिकारी श्याम कुमार ने किया स्कूल अधिकारियों से बहुत प्रशंसा मिली। दिल्ली ब्रिगेड के प्रयास महत्वपूर्ण हैं और जीवनरक्षा, और उनके ज्ञान की स्वीकार्यता उनके महत्व को रेखांकित करती है। यह संपूर्ण शिक्षा में इस जागरूकता को प्रसारित करने की हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है जीएनसीटी दिल्ली में संस्थान, जो वर्तमान परिदृश्य में आवश्यक है।

किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये कॉल करें 9810982008

पुरातत्व विभाग में हो रहा श्रम कानूनों का उल्लघंन - बी एम एस

स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ने केंद्रीय श्रम आयुक्त भारत सरकार से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में वर्षो से कार्य कर रहे सभी अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई करने, चिकत्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा के नाते पेंशन देने की मांग रखी, साथ यूनियन ने बताया कि पुरातत्व विभाग में वर्षो काम करने के बाद भी अस्थाई कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया जाता है जबकि 5 साल से अधिक नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी का पैसा पाने का अधिकार है,

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कर्मचारी को ईएसआईसी, पी एफ और ग्रेच्युटी देने को लेकर 15 अक्टूबर तक अपना लिखित जवाब मुख्य श्रम आयुक्त भारत सरकार को देना है।

इस आदेश के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है, इस कार्यवाही में श्रम संगठन की ओर से भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री डॉ दीपेंद्र चाहर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष संदीप हापसे, सदस्य कैलाश पाटिल, विभाग की ओर से निदेशक प्रशासन सर्वजीत सिंह, अनुभाग अधिकारी उपस्थित रहे।।

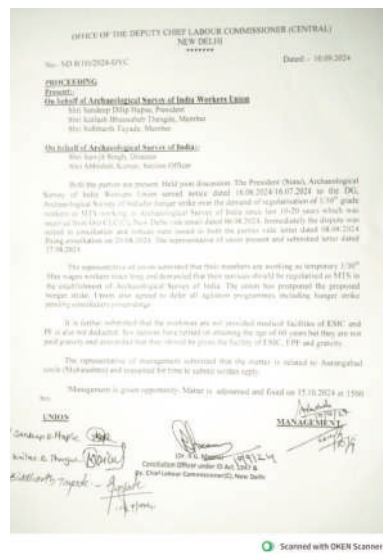

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 'एक्सपोनेंशियल ग्रोथ' के लिए 'मोदी लॉ' पर फोकस करे दुनिया- ग्लोबल लीडर्स

परिवहन विशेष न्यूज

आईमैक के प्रेसीडेंट व सीईओ लूकवॉडन हॉल ने कहा कि हम भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए तैयार है। आईमैक स्ट्रैटिज साझेदारी के लिए तैयार है। यह केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है क्योंकि एक रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए जिसकी कमी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत के अलावा कौन प्रस्तुत कर सकता है।

ग्रेटर नोएडा। भारत अब दुनिया में केवल ग्लोबल लीडर ही नहीं, बल्कि मार्केट की सबसे प्रमुख जरूरत यानी सप्लाई चेन की दिशा में भी दिग्गज बनने की ओर तेजी से बढ़ चला है। आज पूरी दुनिया भारत को न केवल सेमीकंडक्टर विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनते देखना चाहती है बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी प्रमुख भूमिका को लेकर न केवल आश्वस्त है बल्कि इसके लिए सभी तरह के समन्वय के लिए भी प्रतिबद्ध है।

बुधवार को ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2024 में शिरकत करते हुए सेमीकंडक्टर सेक्टर के ग्लोबल लीडर्स ने इन्हीं विषयों पर सबसे ज्यादा फोकस किया। साथ ही, पूरी दुनिया को ग्रोथ के लिए 'मोदी लॉ' पर फोकस करने की नसीहत दी। ये मोदी लॉ दरअसल पीएम मोदी की नीतियां हैं जो किसी भी इंडस्ट्री के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अवसर हैं और पीएम मोदी का विजन इस पर ही सबसे ज्यादा फोकस करता है। इसी बात को ग्लोबल लीडर्स ने सबसे ज्यादा सराहा और प्राथमिकता दी।

मोदी लॉ पूरी दुनिया का मार्ग कर रही प्रशस्त

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ग्लोबल कोलैबोरेशन की दिशा में काम करने ग्लोबल एसोसिएशन सेमी के प्रेसीडेंट व सीईओ अजीत मनोचा ने कहा कि यह अकल्पनीय होने के साथ अद्भुत है। सेमीकॉन कई देशों में आयोजित हो चुके हैं मगर भारत में यह पहला संस्करण है और अन्य देशों की तुलना में यह चार से पांच गुना ज्यादा बड़ा आयोजन है। यह भारत की अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज को दर्शाता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी सीईओ व बिजनेस लीडर्स इस बात पर सहमत हैं कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण व सप्लाई चेन को बढ़ावा मिलना चाहिए। यह भारत की लीडरशिप और विजन के कारण हो सका जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हमें मोदी लॉ की बात करनी होगी। मोदी लॉ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करता है। हमें इस विजन को सच बनाना होगा क्योंकि यह न केवल भारत, न केवल विश्व बल्कि पूरी मानवता की उन्नति का मार्ग है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होने वाली उपलब्धि पूरे इंडस्ट्री सेक्टर में उपलब्धियों के द्वार खोलने का आधार बनती हैं।

20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की तरह मिलकर करना होगा कार्य

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ डॉ. रणधीर ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के पहले कॉमर्शियल फैब का धोलेरा गुजरात व देश की पहली इंडीजीनियस ओसीइएट इंडस्ट्री का जागीरोड़ असम में फाउंडेशन स्टोन रखा। यह दोनों प्रोजेक्ट भारत सरकार से रिकॉर्ड समय के अंदर स्वीकृत हुए जिसने एक बेंचमार्क स्थापित किया है। यह भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत संभव हुआ।

चिप कंडक्टर के निर्माण से हजारों सोफेस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर पार्टनर्स की जरूरत होती है जो टीम की तरह काम करती है। कुल 11 महत्वपूर्ण घटकों के जरिए चिप निर्माण पूरा होता है जिसमें डिजाइन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स व लॉजिस्टिक्स महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत सरकार की पहल से ये सभी जरूरी 11 इकोसिस्टम के प्रतिनिधि कार्यक्रम में सम्मिलित हैं जो एक बड़ी उपलब्धि है। हम सभी पार्टनर्स के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें साथ मिलकर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम की तरह मिलकर कार्य करना होगा।

यह पीएम मोदी के ग्लोबल रीच, विजन व सेमीकंडक्टर मिशन के कारण ही संभव हो पाया है। टाटा ही देश में स्टील इंडस्ट्री लेकर आई थी और अब हम देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। इस प्रक्रिया से हम पचास हजार रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे। प्रत्येक सेमीकंडक्टर रिलेटेड जॉब अपने साथ 10 अन्य रोजगार के अवसरों का माध्यम भी बनेगा। यही समय है सही समय है, भारत का अनमोल समय है।

तीन एट्रीब्यूट्स के जरिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मिलती है सफलता

एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व सीईओ कर्ट सीवर्स ने कहा कि एंबीशन, ट्रस्ट व कोलैबोरेशन वह तीन एट्रीब्यूट्स हैं जिनके जरिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सफलता का मार्ग सुनिश्चित होता है। ये स्प्रिंट नहीं मैराथन है। पचास सालों से हमारी भारत में उपस्थिति है और पिछले कुछ वर्षों में हुआ बदलाव अकल्पनीय है। यह भारत को इकॉनमी के लिहाज से बहुत समृद्ध व ताकतवर बना रहा है। इनोवेशन, डेमोक्रेसी और ट्रस्ट वो मैजिक मंत्र है जिसपर चलकर देश के उद्योग प्रगति करते हैं। हम भारत में हैं, भारत के साथ हैं और प्रतिबद्ध हैं।

भारत में उपस्थिति बढ़ाने पर रेनेसॉ का जोर

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर कंपनी व विश्व की सबसे बड़ी माइक्रोकंट्रोलर सप्लायर के रूप में प्रसिद्ध रेनेसॉ इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के प्रेसीडेंट व सीईओ हितोशी शिबाता ने कहा कि रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स जापान, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इंबेडेड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं। हमें भारत में पहला प्लांट लगाने में सफलता मिली है। हम बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा व हैदराबाद में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहे हैं। दुनिया का पहला 300 मिलीमीटर कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर पाथ हमने ही बनाया था। हमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की जटिलताओं की अच्छे से जानकारी है। हम भारत के इस सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और मोदी लॉ को वास्तविकता बनाने पर कार्य करेंगे।

आईमैक से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में दिखाई रुचि

सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब के तौर पर प्रसिद्ध आईमैक के प्रेसीडेंट व सीईओ, लूकवॉडन हॉल ने कहा कि हम भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए तैयार है। आईमैक स्ट्रैटिज साझेदारी के लिए तैयार है। यह केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है क्योंकि एक रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए जिसकी कमी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत के अलावा कौन प्रस्तुत कर सकता है।

गाजियाबाद में संपत्ति खरीदना हुआ महंगा, DM सर्किल रेट लागू होने के बाद जानें नई कीमतें

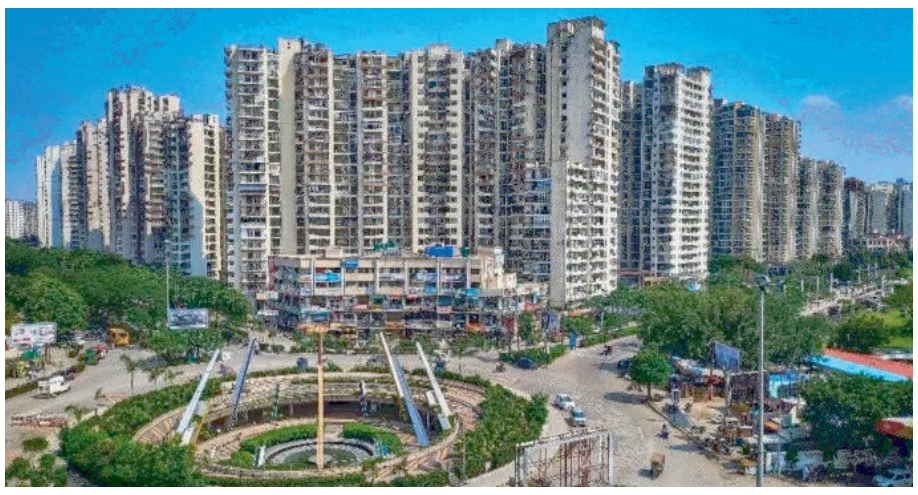

गाजियाबाद में संपत्ति खरीदना अब महंगा हो गया है। नई कीमतें लागू हो गई हैं। बुधवार को डीएम सर्किल रेट की नई दर को लागू जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद कर दिया गया। इससे पहले 13 अगस्त को डीएम सर्किल रेट का प्रस्ताव लाया गया था जिसमें आपत्तियां थी। उन्हें ठीक करने के बाद नए सर्किल रेट लागू कर दिए।

गाजियाबाद। जिले में संपत्ति खरीदना अब महंगा हो गया है। इसकी वजह संपत्ति को लेकर डीएम सर्किल रेट में बढ़ोत्तरी होना है। जिला प्रशासन ने नए डीएम सर्किल रेट की दर को लागू कर दिया है। इसके तहत अब जिले में कृषि भूमि पर एक समान रूप से दस प्रतिशत का सर्किल रेट बढ़ाया गया है।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि 13 अगस्त को प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट को लागू किया गया था, जिसमें 49 आपत्तियां प्राप्त हुईं। आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। किसानों की आपत्ति एक समान रूप से कृषि भूमि पर डीएम सर्किल रेट न बढ़ाने को लेकर थी, ऐसे में अब जिले में सभी कृषि भूमि पर प्रति हेक्टेयर 10 प्रतिशत सर्किल रेट बढ़ाया गया है।

प्रस्ताव सर्किल रेट को किया कम

वेव सिटी और आदित्य वर्ल्ड सिटी में 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर डीएम सर्किल रेट प्रस्तावित किया गया था, आपत्ति मिलने के बाद उसे कम कर वेव सिटी में 40 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर और आदित्य वर्ल्ड सिटी में 35 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से डीएम सर्किल रेट निर्धारित किया गया है। बुधवार को डीएम सर्किल रेट की नई दर को लागू जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद कर दिया गया है।

सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने की साझा प्रेस कांफ्रेंस, बोले- निवेश के अनुकूल माहौल के चलते आज सभी आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश

परिवहन विशेष न्यूज

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश के अनुकूल राज्य बनाने के लिए विगत सात वर्ष में सभी ने काफी मेहनत की है। आज हम निवेशकों की प्रत्येक समस्याओं का निश्चित समय में समाधान करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल निवेश मित्र के जरिए निवेश की प्रक्रिया को सबसे आसान बनाया गया है। पहले भी सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जाती थी लेकिन हमने इसे गंभीरता से लागू किया।

ग्रेटर नोएडा। सेमीकॉन इंडिया 2024 के उद्घाटन के अवसर पर सीएम योगी और केंद्र सरकार के आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने साझा प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के बदले हुए परसेप्शन का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले जहां उत्तर प्रदेश में कोई निवेश नहीं करना चाहता था, वहीं आज उत्तर प्रदेश के बदले हुए परसेप्शन के कारण यहां निवेश के ढेर लगे हैं। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। निवेश के अनुकूल नीतियां हैं। व्यापार के अनुरूप वातावरण है। इसके चलते आज हर कोई उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आना चाहता है।

2017 से 2024 में आया बड़ा बदलाव

2017 के पहले और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश में अंतर को स्पष्ट करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब हम इन्वेस्टर्स समिट की प्लानिंग कर रहे थे तो हमें कहा गया कि सिर्फ 20 हजार करोड़ रुपए तक का ही निवेश संभव हो सकेगा। हालांकि, पिछले साल हमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला। इसमें से इसी वर्ष फरवरी माह तक हमने 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है। यह बदले हुए उत्तर प्रदेश के वर्क कल्चर को दिखाता है।

सेमीकंडक्टर पॉलिसी से निवेशकों की राह होगी आसान

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेश के अनुकूल राज्य बनाने के लिए विगत सात वर्ष में सभी ने काफी मेहनत की है। आज हम निवेशकों की प्रत्येक समस्याओं का निश्चित समय में समाधान करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल निवेश मित्र के जरिए निवेश की प्रक्रिया को सबसे आसान बनाया गया है। पहले भी सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जाती थी, लेकिन हमने इसे गंभीरता से लागू किया। आज किसी भी निवेशक को अपने इंसेंटिव्स के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ऑनलाइन ही सारे काम हो जाते हैं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सेमी कंडक्टर पॉलिसी 2024 को हमने लागू किया है। इसके माध्यम से हम निवेशकों की राह को आसान बना रहे हैं।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से लापता छात्राएं वापस लौटीं, पुलिस कर रही पूछताछ

गाजियाबाद के कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुई तीन छात्राएं वापस लौट आई हैं। तीनों छात्राएं कक्षा सात और कक्षा आठ में पढ़ती हैं। बता दें छात्राओं का पता लगाने के लिए पुलिस की दो टीम लगाई गई थी। स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए थे। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

गाजियाबाद। संदिग्ध हालात में नेहरू नगर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से लापता हुईं तीन छात्राएं बुधवार सुबह वापस लौट आई हैं। यह तीनों छात्राएं मंगलवार सुबह विद्यालय से लापता हुई थीं।

पुलिस की दो टीम कर रही थी तलाश

इसके बाद अफरा तफरी मच गई थी, पुलिस की दो टीमों को छात्राओं की तलाश में लगाया गया था। डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया कि तीनों छात्राएं वापस विद्यालय पहुंच गई हैं। छात्राएं कहां पर गई थीं, इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है।

जल्द ही इसका पता लगाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। तीनों छात्राएं 12 से 16 साल की उम्र हैं। उनके लापता होने की सूचना पर जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पता चला कि सोमवार सुबह पांच बजे तक तीनों छात्राएं विद्यालय में थीं।

कश्मीरी की सोच बताएंगे विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। इसकी भी वजह है कि 24 सीटें पीओके यानि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए हैं।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा लिए 18 सितंबर से एक अक्टूबर 2024 तक तीन चरणों में चुनाव होने हैं। नतीजे आठ अक्टूबर 2024 को घोषित किए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम बताएंगे कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में बडी तादाद में विकास हुआ। शांति लौटी। रोज की होने वाली पत्थरबाजी से जम्मू-कश्मीर की मुक्ति मिली। सिनेमा हाल खुल गए। पर्यटक आने लगे। मुहर्रम के जुलूस निकलने लगे। कश्मीर में बहुत कुछ बदल गया है, इसके बावजूद देखना यह है कि कश्मीर का मतदाता क्या इस विकास को पसंद करता है, या उसे मजहबी कट्टरता ही मंजूर है।

जम्मू-कश्मीर में कुल 114 विधानसभा सीटें हैं लेकिन राज्य में विधानसभा सीटों के डिलिमिटेशन के बाद चुनाव केवल 90 सीटों पर ही होंगे। इसकी भी वजह है कि 24 सीटें पीओके यानि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तनों के कारण इनमें से केवल 90 सीटों के लिए चुनाव होना तय है। वर्ष 2019 में जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो राज्य में चुनावी सीटों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू की। मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। इसकी अंतिम रिपोर्ट मई 2022 में जारी की गई। इस रिपोर्ट ने विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी। इसमें छह सीटें जम्मू और एक कश्मीर में बढ़ी है।114 सीटों में 24 सीटें पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के क्षेत्रों के लिए आरक्षित हैं, इसका अर्थ है कि उन पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए, चुनाव के लिए उपलब्ध सीटों की प्रभावी संख्या 90 है, जम्मू संभाग में 43 और कश्मीर संभाग में 47, राज्य का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद यहां पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं।

राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव दस साल पहले नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। चुनाव के बाद जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने राज्य सरकार बनाई। इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का सात जनवरी 2016 को निधन हो गया। राज्यपाल शासन लगा पर कम समय के लिए लगा। फिर महबूबा मुफ्ती ने वहां मुख्यमंत्री पद के लिए रूप में शपथ ली। पिछली राज्य सरकार से जून 2018 में भाजपा ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया। नवंबर 2018 में, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य विधानसभा भंग कर दी। 20 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

भाजपा की ओर से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी घोषणापत्र जारी किया। इसमें आतंकवाद के सफाए और हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण से लेकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास तक, भाजपा ने कई प्रमुख वादे किए हैं। अमित शाह ने कहा कि यह क्षेत्र में विकास, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पार्टी के वादों और योजनाओं के अनुरूप है।

नए जम्मू और कश्मीर' के लिए 25 वादों में से, भाजपा ने 'जम्मू और कश्मीर को राष्ट्र के विकास और प्रगति में अग्रणी बनाने' के लिए आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करने की कसम खाई। कांग्रेस-नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने और अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले की राजनीतिक स्थिति बहाल करने का भी वादा किया है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलकर तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत का नाम बदलकर कोह-ए-मरान करने की बात कही है। इसे कश्मीर की मुस्लिम बहुल आबादी की भावनाओं को भुनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर के चुनाव के विभिन्न दलों के स्थानीय नेता तो चुनाव प्रचार में उतर ही चुके हैं। बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं की भी सभाएं शुरू हो गई हैं। जनसंपर्क अभियान चल रहा है। रोड शो निकाले जा रहे हैं। घर-घर जाकर नेता लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि कश्मीर घाटी में परिवारवादी दलों के दिन अब खत्म नजर आ रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में जम्मू-कश्मीर के बुनियादी ढांचे का इस तरह विकास किया गया है कि पिछले दिनों श्रीनगर में जी-20 देशों की बैठक शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम भी श्रीनगर में ही आयोजित किया गया। इसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया।

हालात तो ये बता रहे हैं कि कश्मीर बदल रहा है किंतु जम्मू-कश्मीर की बारामुला सीट लोकसभा सीट से आतंकवादियों को फंडिग करने के आरोप में जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख़ की जीत कुछ और ही इशारा कर रही है। उन्होंने जेल में रहते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला को दो लाख से भी ज़्यादा वोटों से शिकस्त दी है। बारामुला सीट पर रशीद को चार लाख 72 हज़ार वोट मिले जबकि उमर अब्दुल्ला को दो लाख 68 हज़ार वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे जम्मू-कश्मीर पीपल्स कऽॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन। उन्हें एक लाख 73 हज़ार वोट मिले। अब्दुल रशीद शेख़ के स्थानीय समर्थक अब्दुल माजिद इस जीत पर बीबीसी से कहते हैं कि साल 2019 के बाद जो कुछ भी कश्मीर में हुआ, इंजीनियर रशीद की जीत उसी बात का जवाब है। उनका कहना था कि कश्मीर के युवाओं ने जिस तरह इंजीनियर रशीद का समर्थन किया है, वो इस बात को दर्शाता है कि नई पीढ़ी नए चेहरों को ढूंढ रही है और पारंपरिक राजनीति से तंग आ चुकी हैं। इंजीनियर रशीद को 'आतंकवाद की फ़ंडिंग' के आरोप में यूएपीए के तहत साल 2019 में गिरफ़्तार किया गया था और इस समय वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। रशीद अवामी इत्तेहाद पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं1 2019 में भी उन्होंने बारामूला से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार उन्होंने बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। जेल जाने से पहले इंजीनियर रशीद शांतिपूर्ण तरीक़े से कश्मीर समस्या को हल करने की वकालत करते रहे हैं। इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के सख़्त ख़िलाफ़ थे और इस मुद्दे को लेकर वह सड़कों पर भी उतरे थे। उन्होंने इसके विरोध में कई धरने भी दिए हैं। सरकार का दावा है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर विकास कि राह पर आगे बढ़ रहा है और जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा भी बार-बार 'नए कश्मीर' की बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में कुछ लोग इसे 'जबरन ख़ामोशी' भी कहते हैं। उनका आरोप है कि किसी को खुलकर बात करने नहीं दी जाती है।

इंजीनियर रशीद को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिल गई है। देखिए क्या होता है। अमेरिका और मित्र देशों ने 20 साल अफगानिस्तान को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए जमकर निवेश किया था, किंतु एक झटके में वह इस्लाम के रास्ते पर चला गया। यही डर है। अभी तो कश्मीर में फौज है। देखना यह है कि बिना फौज के भी कश्मीर का रूख ये ही रहता है, या वह फिर पुराने आतंकवाद के रास्ते पर लौटता है। हालांकि हम भारतीय आशावादी है। आशा करते हैं कि सब ठीक होगा। कश्मीरी नागरिक और युवा नए कश्मीर, विकसित कश्मीर को स्वीकार कर विकास का रास्ता अपनाएगें।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

होंडा एक्टिवा ईवी लॉन्च की तारीख पक्की

परिवहन विशेष न्यूज

टू-व्हीलर सेगमेंट में होंडा की एक्टिवा का अलग ही क्रेज है। अब कंपनी ने एक्टिवा ईवी तैयार कर ली है। लोग इसके लॉन्च का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब इसके लॉन्च पर लेटेस्ट अपडेट आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कूटर को मार्च 2025 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी अगले दो से तीन हफ्तों में इसका ऑन-रोड ट्रायल शुरू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि दिसंबर 2024 में इसके लुक्स से पर्दा उठ जाएगा। जिसके बाद फरवरी या मार्च में इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है।

जानकारी के मुताबिक होंडा ने गुजरात और कर्नाटक में होंडा एक्टिवा ईवी के प्रोडक्शन के लिए अलग से सेटअप तैयार किया है, ताकि इसके वेटिंग पीरियड को कम से कम रखा जा सके। यह भारत में कंपनी का पहला ईवी स्कूटर होगा। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमतों का खुलासा नहीं किया है। अनुमान है कि यह शुरुआती कीमत 1 लाख रुपये एक्स-शोरूम पर पेश की जा सकती है।

होंडा एक्टिवा ईवी में कंपनी दो बैटरी पैक देगी। बताया जा रहा है कि अलग-अलग बैटरी सेटअप पर यह स्कूटर आसानी से 100 से 150 किलोमीटर की रेंज देगा। स्कूटर में सिंगल पीस सीट है, जिससे लंबी दूरी के सफर में इसे चलाना आसान होगा। यह स्कूटर 12 इंच के टायर साइज के साथ उपलब्ध होगा, जो इसे स्टाइलिश लुक देगा।

होंडा एक्टिवा ईवी में राइडर की सुरक्षा के लिए डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। यह स्कूटर फ्रंट में टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ उपलब्ध होगा। इस सस्पेंशन की वजह से टूटी सड़कों पर ड्राइव करना आसान होगा। स्कूटर में युवाओं के लिए आकर्षक कलर ऑप्शन और एलईडी लाइट्स हैं। स्कूटर में बड़ी टेललाइट दी गई है। यह स्कूटर एलॉय व्हील और सिंपल हैंडलबार के साथ आएगा।

एमजी मोटर्स ने एमजी विंडसर ईवी की लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

एमजी मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक गाड़ी एमजी विंडसर ईवी लॉन्च कर दी है। यह इलेक्ट्रिक गाड़ी कई एडवांस्ड फीचर्स, बेहतरीन बैटरी लाइफ और आधुनिक तकनीक से लैस है। एमजी की यह नई पेशकश टाटा नेक्सॉन ईवी और महिंद्रा एक्सयूवी 400 जैसी लोकप्रिय इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

एमजी विंडसर ईवी में 38 kWh क्षमता की दमदार बैटरी दी गई है, जिसे 0 से 100 प्रतिशत तक चार्ज होने में 13.8 घंटे का समय लगता है। फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करके इस बैटरी को 55 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। यह वाहन एक स्थायी सिंक्रोनस मोटर से लैस है, जो 136 पीएस की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करती है। इसकी ड्राइविंग रेंज सिंगल चार्ज पर 331 किलोमीटर तक है, जो इसे लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयुक्त बनाती है।

एमजी विंडसर ईवी की लंबाई 4295 मिमी, चौड़ाई 2126 मिमी और ऊंचाई 1677 मिमी है। इसका व्हीलबेस 2700 मिमी है, जो वाहन के अंदर अच्छी जगह प्रदान करता है। इसके अलावा 604 लीटर का बूट स्पेस और 186 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस इसे एक व्यावहारिक और सुविधाजनक वाहन बनाता है।

विंडसर ईवी में कई एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें एलईडी प्रोजेक्टर हैडलैंप्स, एलईडी डीआरएल, फ्लश डोर हैंडल, और क्रोम फिनिश विंडो बेल्टलाइन शामिल हैं। इसके इंटीरियर में नाइट ब्लैक थीम के साथ गोल्डन टच हाइलाइट्स दिए गए हैं, जो इसे एक प्रीमियम लुक प्रदान करते हैं। इसके अलावा, लैदर-पैक डैशबोर्ड, पैनोरमिक सनरूफ, 10.1 इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले, वायरलैस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स इसे एक लग्जरी फीलिंग देते हैं।

इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में 6 से 9 स्पीकर वाला इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम दिया गया है। वहीं, वेंटिलेटेड एयरो लाउंज सीट्स, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, क्रूज कंट्रोल, और ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल जैसी सुविधाएं इसे और भी आकर्षक बनाती हैं।

सेफ्टी के लिहाज से भी एमजी विंडसर ईवी बेहतरीन विकल्प है। इसमें 6 एयरबैग, हिल असिस्ट, ईएसएस, 360 डिग्री कैमरा, एलईडी कॉर्नरिंग लाइट्स, और रियर फॉग लैंप जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। इसके चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और ऑटो होल्ड की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा, बच्चों की सुरक्षा के लिए आईएसओफिक्स चाइल्ड एंकर भी दिया गया है।

एमजी विंडसर ईवी तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी Excite, Exclusive, और Essence। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू होती है। इस कीमत में बैटरी चार्जिंग की लागत अलग से होगी, जो कि 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। बैटरी की देखरेख और उसकी लाइफ को लेकर ग्राहकों को कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि एमजी मोटर्स बैटरी खराब होने पर विशेष भुगतान योजना भी दे रही है।

एमजी विंडसर ईवी की बुकिंग 3 अक्टूबर से शुरू होगी और डिलीवरी 12 अक्टूबर से की जाएगी। फर्स्ट बायर्स के लिए कंपनी ने लाइफटाइम बैटरी वारंटी के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर की पेशकश की है। साथ ही पहले साल के लिए पब्लिक चार्जिंग की कोई लागत नहीं ली जाएगी।

एमजी विंडर ईवी हुई भारत में लॉन्च, मिलेगी 331KM की रेंज, कीमत 9.9 लाख रुपये से शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

ब्रिटिश वाहन निर्माता MG की ओर से भारतीय बाजार में कई वाहनों की बिक्री की जाती है। कंपनी ने 11 सितंबर को नई इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर विंडसर ईवी (MG Windsor EV Launched In India) को लॉन्च कर दिया है। इसमें कितनी दमदार बैटरी और मोटर को दिया गया है। किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं और इसकी कीमत क्या रखी है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। एमजी मोटर्स की ओर से भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी को लॉन्च कर दिया है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी में किस तरह के फीचर्स दिए गए हैं, कितनी दमदार बैटरी और मोटर को दिया गया है। किस कीमत पर इसे खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्च हुई MG Windsor EV

एमजी मोटर्स की ओर से भारत में नई इलेक्ट्रिक गाड़ी के तौर पर MG Windsor EV को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं, जिसके साथ दमदार बैटरी और रेंज दी गई है।

बैटरी और मोटर

MG Windsor EV में कंपनी की ओर से 38 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया गया है। जिसे 0-100 फीसदी चार्ज करने में 13.8 घंटे का समय लगता है। फास्ट चार्जर के जरिए इसे 55 मिनट में 0-80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है। विंडसर ईवी में परमानेंट सिंकोरियस मोटर दी गई है जिससे 136 पीएस की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। जिससे इसे 331 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

कितनी है लंबाई-चौड़ाई

MG Windsor EV की लंबाई 4295 एमएम, चौड़ाई 2126 एमएम, ऊंचाई 1677 एमएम, व्हीलबेस 2700 एमएम है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 186 एमएम है और इसमें 604 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है।

कैसे हैं फीचर्स

एमजी विंडसर ईवी में एलईडी प्रोजेक्टर हैडलैंप, एलईडी डीआरएल, 17 और 18 इंच के टायर, फ्लश डोर हैंडल, ग्लास एंटीना, क्रोम फिनिश विंडो बेल्टलाइन, नाइट ब्लैक इंटीरियर के साथ गोल्डन टच हाईलाइट्स, लैदर पैक के साथ डैशबोर्ड, ड्राइवर आर्मरेस्ट, डोर ट्रिम, स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। एंबिएंट लाइट्स, रियर एसी वेंट्स, पीएम 2.5 फिल्टर, 10.1 इंच टच डिस्प्ले, सात और 8.8 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 15.6 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूएसबी चार्जर पोर्ट, वायरलैस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, 6 स्पीकर और 9 स्पीकर इनफिनिटी ऑडियो सिस्टम का विकल्प, पैनोरमिक सनरूफ, एयरो लाउंज सीट्स, वेंटिलेटिड सीट्स, 6वे पावर एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, स्मार्ट स्टार्ट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक टेंपरेचर कंट्रोल, वायरलैस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर्स मिलते हैं।

सेफ्टी फीचर्स

विंडसर ईवी में एमजी की ओर से छह एयरबैग, हिल असिस्ट, ईएसएस, 360 डिग्री कैमरा, एलईडी कॉर्नरिंग लाइट्स, रियर फॉग लैंप, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, आइसोफिक्स चाइल्ड एंकरेज, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हैडलैंप, फॉलो मी हैडलैंप जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

कीमत

MG Windsor EV को Exite, Exclusive और Essence वेरिएंट के विकल्प के साथ खरीदा जा सकता है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। 9.99 लाख रुपए सिर्फ गाड़ी की कीमत होगी और बैटरी के लिए अलग से 3.50 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से पेमेंट करनी होगी।

परिवहन विभाग को अवैध ई-रिक्शा और टेंपो के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

रुद्रपुर एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुदृढ़ बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एआरटीओ को अवैध ई-रिक्शा और टेंपो के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार 11 सितंबर को एसएसपी ने अपने कार्यालय में एआरटीओ प्रवर्तन निखिल शर्मा और प्रशासन चक्रपाणि मिश्रा के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-रिक्शा के लिए रूट तय किए जाएं। साथ ही सीएनजी टेंपो का पंजीकरण कम किया जाए। नगर क्षेत्र में ई-रिक्शा के लिए स्टैंड चिह्नित करने के लिए नगर निगम से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

गाजियाबाद में गरीब ई-रिक्शा संचालकों में खुशी की लहर

मीडिया की खबर का जोरदार असर, शहर में दो रूटों पर ई-रिक्शा संचालन शुरू हो गया। सीपी ने दो रूटों पर ई-रिक्शा संचालन बंद कर दिया था। मीडिया ने गरीब ई-रिक्शा चालकों का दर्द दिखाया। दोपहर में भाजपा विधायक ने भी समर्थन किया। शाम को विधायक नंद किशोर गुर्जर ने समर्थन किया। सीपी ने अपना फैसला वापस ले लिया। गरीब ई-रिक्शा संचालकों में खुशी की लहर। गाजियाबाद में मीडिया की खबर का जोरदार असर।

प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद, दि0 11.09.24

गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ एवं सुचारु बनाये रखने तथा जाम की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से दिनांक 12.09.2024 से अम्बेडकर रोड पर पुराना बस अड्डा बाया मालीवाडा चौक, कालकागढी चौक होते हुए चौधरी मोड तक ई-रिक्शा का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया था। आज एक प्रतिनिधि मण्डल, जिसमे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, गाजियाबाद ई-रिक्शा एसोसिएशन के प्रतिनिधि, गाजियाबाद व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि , पार्षदगण आदि शामिल थे, द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि इस प्रतिबन्ध से सामान्यजनों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पडेगा तथा व्यापारियों के व्यापार पर भी असर होगा। उक्त बातों का संज्ञान लेते हुए दिनांक 12-09-2024 से लागू किये गये प्रतिबन्ध को जनहित मे तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।

टाटा ने इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें 3 लाख रुपये तक घटाईं, पंच ईवी 10 लाख रुपये से सस्ती

परिवहन विशेष न्यूज

फेस्टिवल सीजन शुरू होते ही टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में भारी कटौती कर ग्राहकों को चौंका दिया है। सोमवार, 09 सितंबर को अपनी टियागो, टिगोर, नेक्सन और सफारी-हैरियर के आईसी इंजन और सीएनजी वेरिएंट की कीमतों में भारी कटौती के बाद अब टाटा ईवी ने फेस्टिवल ऑफ कार्स ऑफर के तहत टियागो ईवी, पंच ईवी और नेक्सन ईवी की कीमतों में 3 लाख रुपये तक की कटौती की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंपनी ने नेक्सन ईवी की कीमत में 3 लाख रुपये तक की कटौती की है। वहीं नेक्सन ईवी की शुरुआती कीमत अब 10 लाख रुपये से भी कम हो गई है। टाटा ने एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी की कीमत में भी काफी कटौती की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आपको पेट्रोल-डीजल कारों की कीमत में इलेक्ट्रिक कारें मिल जाएंगी। टाटा की इलेक्ट्रिक कारों को आप 31 अक्टूबर तक कम कीमत में खरीद सकते हैं।

टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार पंच ईवी की कीमत में 1.20 लाख रुपये की कटौती की गई है, जिसके बाद अब पंच ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 9,99,000 रुपये हो गई है।

टाटा मोटर्स ने फेस्टिवल ऑफ कार्स ऑफर के तहत अपनी सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार नेक्सन ईवी की कीमत 3 लाख रुपये कम कर दी है। अब टाटा नेक्सन ईवी की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 12.49 लाख रुपये हो गई है। किसी ने नहीं सोचा था कि टाटा मोटर्स फेस्टिव सीजन में अपनी नेक्सन ईवी की कीमत इतनी कम कर सकती है।

टाटा मोटर्स के साथ ही कंपनी ने देश की सबसे सस्ती एसयूवी में से एक टियागो ईवी की

चाबियां सौंपने पीएम के संसदीय कार्यालय पहुंचे ई-रिक्शा चालक

परिवहन विशेष न्यूज

बारकोड और रूट वाइज व्यवस्था से नाराज ई-रिक्शा चालकों और जिला प्रशासन के बीच वार्ता विफल रही। बुधवार 11 सितंबर को नौ हजार ई-रिक्शा चालक अपने वाहनों की चाबियां सौंपने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पहुंचे। इस दौरान चालकों ने जमकर नारेबाजी की।

इससे पहले मंगलवार 10 सितंबर को छठे दिन भूख हड़ताल पर बैठे ई-रिक्शा चालकों ने चाबियां सौंपने का एलान किया था। दोपहर में सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा और पूर्व महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने शास्त्री घाट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन पत्र सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि प्रशासन ने मांग नहीं मानी तो अखिलेश यादव वाराणसी आकर आंदोलन में शामिल होंगे।

ऑल इंडिया ई-रिक्शा चालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण काशी ने बताया कि चालकों के मना करने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस होमगार्ड और टीआई के जरिए जबरन ई-रिक्शा को ट्रैफिक कार्यालय ले गई और बार कोड लगवा दिया। उन्होंने कहा कि बिना सहमति के बार कोड लगाया जा रहा है। कई वाहन चालक अज्ञानतावश अपने वाहन पर स्टीकर लगवा रहे हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर के दायरे में वाहन चालक क्या कमाएंगे। वे अपने बैंक की किश्तें नहीं भर पाएंगे। इससे गलियों में रहने वाले लोगों को भी दिक्कत होगी।

पशु कल्याण और नैतिक कृषि पद्धतियों का बढ़ता महत्व

विजय गर्ग

पशुधन पालन और जैविक खेती कृषि विकास के अभिन्न अंग रहे हैं। सफलता के साथ-साथ, राज्य में जानवरों के उचित और मानवीय उपचार को लेकर कई चिंताएँ भी उठती हैं। भारत के कई हिस्सों, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में ऊबड़-खाबड़ इलाके हैं, जिन्हें बैल जैसे बोझा ढोने वाले जानवरों द्वारा समतल किया जाता है। उचित देखभाल के बिना इन जानवरों के लगातार उपयोग से थकान, चोट और कुपोषण हो सकता है।

पशुधन पालन और जैविक खेती कृषि विकास के अभिन्न अंग रहे हैं। सफलता के साथ-साथ, राज्य में जानवरों के उचित और मानवीय उपचार को लेकर कई चिंताएँ भी उठती हैं। भारत के कई हिस्सों, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में ऊबड़-खाबड़ इलाके हैं, जिन्हें बैल जैसे बोझा ढोने वाले जानवरों द्वारा समतल किया जाता है। उचित देखभाल के बिना इन जानवरों के लगातार उपयोग से थकान, चोट और कुपोषण हो सकता है। इसके अलावा, छोटे पैमाने पर डेयरी फार्मिंग प्रथाओं में, जो राज्य में आम हैं, जानवरों के लिए खराब पोषण, साफ पानी की कमी और अपर्याप्त आश्रय जैसे मुद्दे बने रहते हैं। इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में, पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच सीमित है, जिससे अनुपचारित बीमारियाँ और खराब पशु स्वास्थ्य होता है। इन मुद्दों से निपटने के लिए, यह लेख पशु कल्याण के महत्व और नैतिक खेती पर इसके लाभों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करेगा। भारत में पशु कल्याण और नैतिक खेती में सुधार के प्रयासों को स्थायी कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षा बढ़ाने, पशु चिकित्सा देखभाल तक पहुंच में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि पर्यावरणीय स्थिरता के लिए राज्य की समग्र प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में कृषि जानवरों और वन्यजीवों दोनों के साथ नैतिक रूप से व्यवहार किया जाए। जैसे-जैसे वैश्विक खाद्य उद्योग विकसित हो रहा है, ध्यान इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि खेत जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। महिला-केंद्रित योजनाएं: प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की प्रगति की धड़कन भूस्खलन पशु कल्याण अब एक परिधीय चिंता का विषय नहीं है - यह खेती के भविष्य के लिए केंद्रीय है। नैतिक कृषि प्रथाएं, जो पशुधन की भलाई को प्राथमिकता देती हैं, न केवल जानवरों के मानवीय उपचार के लिए आवश्यक हैं, बल्कि बढ़ी हुई उत्पादकता और अधिक बाजार अपील सहित किसानों के लिए ठोस लाभ भी प्रदान करती हैं। पशु कल्याण क्यों मायने रखता है? इसके मूल में, पशु कल्याण यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि खेत जानवरों को ऐसी परिस्थितियों में पाला जाए जो उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करती हों। इसका मतलब है पर्याप्त स्थान, स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और पशु चिकित्सा देखभाल तक पहुंच प्रदान करना। इसके अतिरिक्त, इसमें ऐसे वातावरण बनाना शामिल है जहां जानवर प्राकृतिक व्यवहार में संलग्न हो सकें जैसे कि चरागाहों में चरने वाली गायें, स्वतंत्र रूप से घूमने वाली मुर्गियां, और मिट्टी में रहने वाले सूअर। शोध से पता चला है कि जब जानवरों को ऐसे वातावरण में पाला जाता है जो उनकी भलाई को प्राथमिकता देता है, तो वे अधिक स्वस्थ और अधिक उत्पादक होते हैं। उदाहरण के लिए, जिन गायों को स्वतंत्र रूप से चरने की अनुमति दी जाती है, वे अक्सर उच्च गुणवत्ता का अधिक दूध पैदा करती हैं। इसी तरह, मानवीय

परिस्थितियों में पाली गई मुर्गियों में बीमारी का खतरा कम होता है, जिससे अंडे का उत्पादन बेहतर होता है। संक्षेप में, जब जानवर फलते-फूलते हैं, तो खेत भी फलते-फूलते हैं। भारत में, कई संगठन पशु स्वास्थ्य और नैतिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं:1. पीपल फॉर एनिमल्स (पीएफए): जानवरों को बचाता है, आश्रय स्थल चलाता है, आवारा कुत्तों के लिए नसबंदी/टीकाकरण अभियान चलाता है, और पशु अधिकारों और क्रूरता की रोकथाम की वकालत करता है।2. एंटी-रेबीज और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम: एक सरकारी-अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो रेबीज नियंत्रण, सड़क कुत्तों के टीकाकरण, नसबंदी और मानवीय उपचार पर सार्वजनिक शिक्षा पर केंद्रित है।3. पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाएँ पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करती है, नैतिक पशुधन खेती को बढ़ावा देती है, और कृषि पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। नैतिक खेती के तत्व नैतिक खेती जानवरों की बुनियादी देखभाल से परे है - इसमें खेती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण शामिल है जो पर्यावरण, समाज और स्वयं जानवरों पर प्रभाव पर विचार करता है। नैतिक खेती के कुछ प्रमुख घटकसम्मिलित करें:1. मानवीय प्रबंधन: नैतिक फार्म उन प्रथाओं से बचते हैं जो जानवरों को अनावश्यक तनाव या नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे परिवहन और वध के दौरान भीड़भाड़ या कठोर हैंडलिंग।2. चारागाह-आधारित प्रणालियाँ: जानवरों को खुले स्थानों में स्वतंत्र रूप से चरने और घूमने की अनुमति देने से न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि खेत में मिट्टी के स्वास्थ्य और जैव विविधता में भी वृद्धि होती है।3. जैविक और प्राकृतिक आहार: नैतिक फार्म अक्सर जैविक आहार पर जोर देते हैं, एंटीबायोटिक दवाओं और सिंथेटिक हार्मोन के उपयोग से बचते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि जानवरों को प्राकृतिक आहार तक पहुंच मिले।4. सम्मानजनक वध: मानवीय वध प्रथाओं को अपनाना नैतिक खेती का एक प्रमुख पहलू है, यह सुनिश्चित करना कि जानवरों के साथ जीवन भर सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। किसानों के लिए लाभ नैतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से न केवल जानवरों का सही इलाज होता है, बल्कि इससे किसानों को महत्वपूर्ण लाभ भी होता है। स्वस्थ, कम तनावग्रस्त जानवर उच्च उत्पादकता प्रदर्शित करते हैं, जिससे बेहतर विकास दर, उच्च पैदावार और इस प्रकार उत्पादकता में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए: तनाव मुक्त सूअरों की दक्षता बेहतर होती है और अच्छी तरह से उपचारित डेयरी गायें अधिक दूध देती हैं। किसानों के लिए एक और फायदा यह है कि वे उच्च मूल्य वाले बाजारों में प्रवेश कर सकते हैं जहां ग्राहक 'प्रमाणित मानवीय' और 'पशु कल्याण स्वीकृत' जैसे लेबल के लिए अतिरिक्त भुगतान करने को तैयार हैं। इस बढ़ते बाजार से किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, नैतिक कृषि पद्धतियाँ किसी खेत की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती हैं। जो किसान पशु कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, वे ग्राहकों, खुदरा विक्रेताओं और यहां तक कि पशु कल्याण संगठनों के साथ मजबूत संबंध बना सकते हैं, जिससे व्यापार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। चुनौतियों पर काबू पाने के लिए नैतिक कृषि पद्धतियों में बदलाव के लिए समय, धन और प्रयास के निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए: अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए सुविधाओं को अपग्रेड करना या नई फीडिंग प्रणाली लागू करना महंगा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, सीखने के लिए बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि किसान नई विधियों और प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं। हालाँकि, दीर्घकालिक लाभ-नैतिक और आर्थिक दोनों-इन प्रारंभिक चुनौतियों से अधिक हैं। नैतिक कृषि पद्धतियों से अधिक लचीला कृषि संचालन, उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संबंध और मजबूत बाजार उपस्थिति हो सकती है। निष्कर्षत:, पशु कल्याण और नैतिक कृषि पद्धतियाँ अब केवल प्रवृत्तियाँ नहीं रह गई हैं, वे ऐसे मानक बन रहे हैं जिनके आधार पर आधुनिक खेतों का मूल्यांकन किया जाता है। इन प्रथाओं को अपनाकर किसान न केवल अपने पशुओं के जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी आजीविका भी बढ़ा सकते हैं। जैसे-जैसे नैतिक रूप से उत्पादित भोजन की उपभोक्ता मांग बढ़ती जा रही है, जो लोग इन प्रथाओं को अपनाएंगे वे आने वाले वर्षों में फलने-फूलने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे।

संपादकीय

राहुल का 'भारत विरोध'

यह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पुरानी आदत है। यह उनकी राजनीति का हिस्सा भी है अथवा कुछ विदेशी ताकतें ऐसा करने को उन्हें उकसाती रही हैं। करीब 7-8 साल से राहुल गांधी विदेशी सरजमीं से भारत के खिलाफ विषवमन करते रहे हैं। यदि वह आरएसएस, भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ही टिप्पणियां करें, तो उन्हें राजनीति मान कर नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन वह भारत-विरोध की तथ्यहीन, अज्ञानी, अपरिपक्व टिप्पणियां करेंगे, तो बेशक उसे 'देश-विरोध' ही समझा जाए और सरकार गंभीरता से ग्रहण कर निर्णय ले और उचित कार्रवाई करे। अब राहुल गांधी महज एक सांसद ही नहीं, बल्कि लोकसभा में 'नेता प्रतिपक्ष' हैं। वह संवैधानिक पद पर हैं और ऐसे राजनेता को 'छाया प्रधानमंत्री' आंका जाता है। यदि एक संवैधानिक व्यक्ति ही देश को अपमानित करेगा, चीन की तुलना में 'बौना' करार देगा और गलत तुलनात्मक विश्लेषण करेगा, तो यह देश, समाज और सरकार को उसे 'अक्षम्य' मानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति देश, संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। आजकल राहुल गांधी अमरीका में हैं। वह साक्षात्कार दे रहे हैं और विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। क्या गलत तथ्य पेश कर रहे हैं और नई पीढ़ी को भ्रमित कर रहे हैं? दरअसल भारत के बारे में उनकी सोच ही गलत और पूर्वाग्रही है। वह भारत के मूल विचार को ही नहीं जानते। उनके अनुसार, भारत विचारों की विविधता वाला देश है। अमरीका की तरह राज्यों का संघ है। शायद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद एक में जो परिभाषा दी गई है, उसे नहीं पढ़ा। पढेंगे नहीं, तो समझेंगे कैसे? उसमें भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र परिभाषित किया गया है। संघीय चरित्र और ढांचा होने के कारण उस राष्ट्र में कई राज्य भी हैं, लेकिन वे निरंकुश नहीं हैं। भारत सरकार ही संवैधानिक तौर पर उन्हें संचालित करती है। अलबत्ता राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा रोजगार का उठाया और दावा किया कि चीन, वियतनाम आदि कुछ देशों में 'बेरोजगारी की समस्या' ही नहीं है, जबकि अमरीका समेत पश्चिमी देशों और भारत में बेरोजगारी एक विकट समस्या है। यहां विश्व बैंक के आंकड़े गौरतलब लगते हैं, क्योंकि 2023 में चीन की बेरोजगारी दर 4.7 फीसदी थी, जबकि भारत में यही दर 4.2 फीसदी थी। यानी चीन में बेरोजगारी, भारत की तुलना में, अधिक रही है।

वहां का एक ही उदाहरण पर्याप्त है कि 2 लाख नौकरियों के लिए करीब 77 लाख चीनियों ने आवेदन किया था। हम मानते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में चीन वैश्विक स्तर पर प्रभुत्व की स्थिति में है, लेकिन भारत भी आज 'एप्पल' और 'आईफोन 16' सरीखे अंतरराष्ट्रीय उत्पादों को बना रहा है। अब दुनिया भर में यही भारत-निर्मित उत्पाद सप्लाई किए जाएंगे और उन पर 'मेक इन इंडिया' अंकित होगा। सवाल है कि विदेशी मंचों पर राहुल गांधी, भारत के बारे में, गलत तथ्य पेश क्यों करते रहे हैं? यही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय राजनीतिक प्रणालियों और पार्टियों में प्रेम, सम्मान और विनम्रता का अभाव है। यदि ऐसा है, तो राहुल की पार्टी कांग्रेस भी इसी जमात में शामिल है, क्योंकि वह तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। गजब बयान तो यह रहा, जब राहुल गांधी ने देवता और भगवान की परिभाषा ही बदल दी। परोक्ष रूप से उन्होंने सनातन धर्म की गरिमा को खंडित किया है। राहुल का आरएसएस के प्रति विद्वेष सनातन रहा है। दरअसल वह संघ को न तो जानते हैं और न ही उसकी गहनता तक कभी देख पाएंगे। राहुल समेत कांग्रेस में एक तबके का मानना है कि संघ और भाजपा पारंपरिक तौर पर महिला-विरोधी हैं। राहुल 'दुर्गावाहिनी' की भूमिका नहीं जानते, जो संगठन संघ के साथ काम करता रहा है। उसकी महिलाओं ने सहकारी और स्व सहायता समूहों के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। भाजपा में भी महिला मोर्चा है, जिसमें लाखों महिलाएं सक्रिय हैं। भाजपा का गठन 1980 में हुआ था, जिसकी अभी तक 4 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और सबसे पुरानी पार्टी की 5 ही महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। चलो, यह लड़ाई उनकी परंपरागत है। हमारा सरोकार भारत के संदर्भ में है। क्या विषवमन जारी रहना चाहिए?

विदेश में अध्ययन की सफलता के लिए कैरियर परामर्श महत्वपूर्ण क्यों है?

विदेश में पढ़ाई के लिए कैरियर परामर्श आवश्यक है क्योंकि यह छात्रों को उनके शैक्षणिक और व्यावसायिक पथों के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। यह सही पाठ्यक्रमों, विश्वविद्यालयों और देशों का चयन करने, उनके लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करता है। परामर्शदाता प्रवेश आवश्यकताओं, वित्तीय योजना और छात्रवृत्ति के अवसरों को समझने में सहायता करते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है। वे सांस्कृतिक अनुकूलन और दीर्घकालिक कैरियर संभावनाओं में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को भविष्य के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर, परामर्श से शैक्षणिक सफलता और बेहतर नौकरी प्लेसमेंट की संभावना बढ़ जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र विदेश में पढ़ाई के दौरान अपनी क्षमता का अधिकतम लाभ उठा सकें। छात्रों को उनकी शैक्षणिक स्ट्रीम और पाठ्यक्रम चुनने में मार्गदर्शन करने के लिए ग्रेड 8 से 11 में मानकीकृत इन-हाउस साइकोमेट्रिक मूल्यांकन का उपयोग करें। जीवन कौशल और विभिन्न प्रोफ़ाइल-निर्माण गतिविधियों को शामिल करके प्रत्येक छात्र के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करें, जिससे उन्हें अपनी क्षमता को अधिकतम करने में मदद मिलेगी। रुचि के कार्यक्रम की पहचान करने के लिए एक कार्यक्रम समीक्षा सत्र आयोजित करें। ऐसे विश्वविद्यालयों का चयन करने में सहायता करें जो प्रत्येक छात्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों, स्थान, अनुकूलता और कार्यक्रम रैंकिंग पर विचार करते हुए निवेश पर सर्वोत्तम और अधिकतम रिटर्न सुनिश्चित करें। प्रत्येक छात्र के लिए अधिकतम छात्रवृत्तियाँ सुरक्षित करने के लिए प्रवेश प्रक्रिया का समर्थन करें। किसी छात्र के लिए सबसे उपयुक्त विश्वविद्यालय का निर्धारण करते समय आप किन प्रमुख कारकों पर विचार करते हैं? सर्वोत्तम मूल्य, कार्यक्रम का विकल्प, कार्यक्रम रैंकिंग, उपलब्ध छात्रवृत्ति, शिक्षा की गुणवत्ता, स्नातकोत्तर परिणाम और समग्र शैक्षिक अनुभव जैसे कारक। छात्र के लक्ष्य विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के अनुरूप होने चाहिए। विश्वविद्यालय को अपने स्थान और छात्र के भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निवेश पर मजबूत रिटर्न प्रदान करना चाहिए। पीजी उम्मीदवारों को विदेश में शीर्ष विश्वविद्यालयों के लिए एक मजबूत प्रोफ़ाइल बनाने में मदद करने के लिए आप क्या रणनीतियाँ अपनाते हैं? अकादमिक रिकॉर्ड, कार्य अनुभव, इंटर्नशिप और अनुसंधान परियोजनाओं का मूल्यांकन करें, फिर उन शक्तियों और क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। प्रासंगिक कौशल और प्रमाणपत्र, अनुसंधान और परियोजनाओं और इंटर्नशिप के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करें, पाठ्येतर भागीदारी का सुझाव दें और कार्यक्रम के साथ उनकी पृष्ठभूमि को संरेखित करके व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर काम करें। कार्यक्रम की पसंद के आधार पर प्रोफ़ाइल निर्माण रणनीति प्रत्येक पीजी छात्र के लिए अलग और वैयक्तिकृत है क्या आप प्रोफ़ाइल-निर्माण प्रक्रिया में पाठ्येतर गतिविधियों के महत्व पर चर्चा कर सकते हैं? विविध गतिविधियों में संलग्न होने से न केवल व्यक्तिगत विकास बढ़ता है बल्कि शीर्ष क्रम के विश्वविद्यालयों में आवेदन के लिए आपकी प्रोफ़ाइल भी मजबूत होती है। परामर्शदाता मजबूत, वैयक्तिकृत प्रोफाइल बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो प्रत्येक छात्र के लिए सर्वोत्तम कार्यक्रमों और विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धी अनुप्रयोगों को सुनिश्चित करते हैं और उन्हें कॉलेज के लिए तैयार करते हैं। जुनूनी परियोजनाओं, सामुदायिक सेवा, मॉडल यूनाइटेड नेशंस (एमयूएन), इंटर्नशिप, क्विज़ और शोध कार्य जैसी गतिविधियों में भाग लेने से आत्मविश्वास बनाने और मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलती है। योग्य परामर्शदाता अपने छात्रों के बायोडाटा में मूल्यवान शैक्षणिक और सह-पाठ्यचर्या संबंधी उपलब्धियों को जोड़ने के लिए नए तरीके खोजने के लिए नवाचार करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दुनिया के अपने पसंदीदा क्षेत्रों में अपने सर्वोत्तम रैंक वाले कार्यक्रमों से प्रवेश और छात्रवृत्ति दोनों प्रस्तावों के लिए प्रतिस्पर्धी आवेदक बनें। सर्वोत्तम विश्वविद्यालय. EduVelocity ही नहींछात्रों को उनके सबसे उपयुक्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन जीवन कौशल विकास और प्रोफ़ाइल निर्माण पर काम करने के लिए उच्च प्रशिक्षित और शिक्षित मनोवैज्ञानिकों और परामर्शदाताओं के साथ दीर्घकालिक जुड़ाव पर भी जोर दिया गया है। मनोविज्ञान में स्नातक डिग्री वाले एडुवेलोसिटी के अनुभवी शिक्षकों के पास साइकोमेट्रिक परीक्षण, करियर विकास, समय प्रबंधन कौशल, जीवन कौशल विकास और साक्षात्कार की तैयारी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों में आवेदन करते समय छात्रों को किन अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और आप इन चुनौतियों से निपटने में उनकी मदद कैसे करते हैं? छात्र अक्सर सटीक जानकारी की कमी और गलत सलाह के कारण संघर्ष करते हैं। सही कार्यक्रम की पहचान करना जो छात्र की योग्यता और विषय की पूर्वापेक्षाओं से मेल खाता हो, क्योंकि सभी छात्र इस बात से अवगत नहीं हैं कि अधिकांश कार्यक्रमों के लिए हाई स्कूल के 4 वर्षों के दौरान गणित एक अनिवार्य आवश्यकता है। साक्षात्कार के लिए तैयारी करने और आवेदनों में खुद को अच्छी तरह प्रस्तुत करने में चुनौतियाँ। निबंधों में स्वयं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में कठिनाई। एक कठोर स्कूल पाठ्यक्रम आवश्यक प्रोफ़ाइल-निर्माण गतिविधियों के लिए बहुत कम समय छोड़ता है। समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में संघर्ष करता है। आप अपने मार्गदर्शन कार्यक्रमों की सफलता को मापने के लिए किन मैट्रिक्स या संकेतकों का उपयोग करते हैं? 5 चर के संदर्भ में छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त, अर्थात, कार्यक्रम-विशिष्ट रैंकिंग, फंडिंग और छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालय की गुणवत्ता, समुदाय, आकार आदि, स्थान, और बच्चे की शैक्षणिक और सह-पाठ्यचर्या प्रोफ़ाइल के आधार पर। जीवन कौशल विकास के लिए, हम एक प्रगति रिपोर्ट का उपयोग करते हैं जिसे हमने स्वयं बनाया है और माता-पिता और छात्रों द्वारा मान्य किया गया है। बच्चे के समग्र विकास पर माता-पिता और छात्रों से प्रतिक्रिया एकत्र करना, और सही कार्यक्रम मार्गों की पहचान करने में मदद करना। इसमें ऐसे करियर ढूंढना शामिल है जो न केवल बच्चे की रुचि रखते हों बल्कि उनकी शक्तियों के अनुरूप भी हों, जैसा कि साइकोमेट्रिक परीक्षण और उनकी व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से अन्य उपलब्ध जानकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है।

हिमालय के साथ दृढ़ता से खड़े होने का दिन

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में वाडिया इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, आईआईटी रुडक़ी, इंडियन रिमोट सेंसिंग, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आदि हिमालय को और अधिक करीब से समझने, वहां लगातार हो रहे बदलाव और दुष्प्रभावों पर अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में जलवायु के बदले मिजाज, चमकदार ग्लेशियरों का बिखराव और अन्य खतरों के साथ संस्थाओं की जांच-पड़ताल का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। साल में एक बार ही सही, हिमालय दिवस पर विशेषज्ञों के तर्क, विचार और सलाह आने वाले खतरों से चेता रहे हैं

नौ सितंबर को हिमालय दिवस मनाया गया। यह दिन हिमालय के साथ दृढ़ता से खड़े होने का है। हिमालय की उपयोगिता और महत्व को समस्त हिमालय क्षेत्र बखूबी समझता है। पहाड़ के लोग हमेशा से हिमालय की दृढ़ता कैसे कायम रहे, इसे लेकर दृढ़ रहे हैं। उन्हें जन्म से पर्यावरण के साथ संतुलन साधने का अभ्यास जो है। नदियों की अविरलता और निर्मलता का एहसास है। उनके लिए निर्जन हिमालय तप का साधन है। जंगल और पहाड़ उसके देवता हैं। यही कारण है कि हिमालयी राज्यों के लिए हिमालय के मायने दुनिया से अलग हैं। हिमालय भले ही दुनिया के लिए जल मीनार, तीसरा ध्रुव और किसी के मस्तक का ताज हो सकता है, लेकिन हिमालयी राज्यों के दिल की धडक़न है। दुनिया के देशों के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रकृति की छेड़छाड़ से उपजी उन तमाम मानवीय चिंताओं को उठाने का दिवस और माध्यम है, लेकिन हिमालय दिवस हर लिहाज से हिमालयी राज्यों के ज्यादा करीब है। हिमालय को लेकर उत्तराखंड की चिंता नई नहीं हैं। हिमालय सिर्फ सुदूर डटकर खड़े रहकर सभ्यता की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि पहाड़ के जनजीवन, स्वास्थ्य, कृषि से सीधा जुड़ाव है। यह प्रकृति को बचाए और बनाए रखने के साथ हिमालयी राज्यों को प्रतिकूल मौसम से भी सुरक्षित बनाए रखे हुए है।

हिमालय का गुणगान होना चाहिए

शायद इसीलिए उत्तराखंड ने एक दिन चुना है हिमालय के गुणगान के लिए। हिमालय दिवस देश-दुनिया की जुबान पर कुछ वर्षों से ही चढ़ा है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर बीते पांच-छह वर्षों से हिमालय के सरोकार पर चर्चा और बचाने का संकल्प मजबूत हुआ है। उत्तराखंड इकलौता राज्य है, जहां से हिमालय दिवस की अवधारणा ने सत्तर के दशक में जोर पकड़ा और लगातार पैरवी में जुटा हुआ है। 1973 में जिस तरह 24 सौ पेड़ बचाने के लिए गौरादेवी आगे आईं और कुछ अन्य महिलाओं के साथ उन्हें कटने से बचा लिया। वहीं, सुंदर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत व हिमालय नीति अभियान के सर्वेसर्वा कुलभूषण उपमन्यु आदि ने उस दौर में हिमालय की रक्षा के लिए प्रयास किए, जब दुनिया आने वाले खतरे से अनभिज्ञ थी। इस दौर में भी हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के अनिल जोशी आदि कई नाम हैं, जो नई पीढ़ी को आने वाले खतरों के प्रति सचेत कर रहे हैं, क्योंकि वे सब जानते हैं कि हिमालय उनके लिए कोई पर्वतमाला मात्र नहीं, एक जीवंत सभ्यता, संस्कृति व आत्मिक दर्शन है जिस पर आया कोई भी संकट स्वयं इस क्षेत्र की मानव जाति के अस्तित्व पर खतरा है। भारत की जीवनदायनी गंगा को यूं ही मां गंगा कह कर संबोधित नहीं करते, अपनी बहुआयामी उपयोगिता के कारण वह सचमुच मां ही है।

अनदेखे खतरों को समझने और समझाने का प्रयास

संस्थाएं हिमालय दिवस के बहाने हर साल मानवता के भविष्य के खतरों, चिंताओं और मुद्दों से दुनिया को रूबरू करा रही हैं। राज्य ने 2014-15 में हिमालय दिवस को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। तब से यहां की सरकारें, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हिमालय दिवस में छुपे गूढ़ अर्थ के साथ हिमालय से जुड़े अनदेखे खतरों को समझने और समझाने का प्रयास कर रही हैं। यह सच है कि छोटे से प्रयास ने हिमालयी राज्यों को आने वाले खतरों के प्रति सचेत और एकजुट कर दिया है, लेकिन अभी तालमेल का अभाव स्पष्ट दिखता है। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के पास

जरूरी आंकड़े और पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। हिमालय के करीब वनस्पति के बदलाव, मौसम के खतरे, आपदा की पूर्व चेतावनी, उपग्रह से तस्वीरें आदि महत्वपूर्ण पहलुओं पर बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन तालमेल और जानकारियां साझा न होने से सभी प्रयास बिखरे से दिखते हैं।

चमकदार ग्लेशियरों का बिखराव

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में वाडिया इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, आईआईटी रुडक़ी, इंडियन रिमोट सेंसिंग, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ज्यूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आदि हिमालय को और अधिक करीब से समझने, वहां लगातार हो रहे बदलाव और दुष्प्रभावों पर अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में जलवायु के बदले मिजाज, चमकदार ग्लेशियरों का बिखराव और अन्य खतरों के साथ संस्थाओं की जांच-पड़ताल का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। संवेदनशील उपकरणों से लैस तकनीकी लैब से निकल रहे निष्कर्ष, विषम परिस्थितियों में जमीनी पड़ताल, शोधपत्रों में खंगाली गई जानकारियों का भंडार हैं। साल में एक बार ही सही, हिमालय दिवस पर विशेषज्ञों के तर्क, विचार और सलाह आने वाले खतरों से चेता रहे हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक जरूरी है आमजन की भागीदारी। समय है संस्थाओं के वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देकर इस दिन को जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के रूप में भी याद रखा जाए।

यह भी कहना चाहूंगा कि हिमालय पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उनको दूर करने तथा समाधान करने की सख्त जरूरत है। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने एक किताब में कई ऐसे ही खतरों से सचेत किया है। उनकी इस किताब का नाम है : हिमालय पर लाल छाया। यह किताब काफी पहले लिखी गई थी, लेकिन खतरे आज भी बरकरार हैं। उनकी चिंताओं को संबोधित करने की जरूरत है। वास्तव में हिमालय की धन संपदा, उसके सौंदर्य और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काफी कुछ किया जाना अभी शेष है। इसके लिए हिमालयी राज्यों को एकजुट होना चाहिए। केंद्र सरकार से आशा है कि वह हिमालयी राज्यों की समस्याओं और चिंताओं का समाधान करेगी। इन समस्याओं के समाधान के लिए हिमालयी राज्यों को एकजुट होकर योजनाबद्ध प्रयास करने चाहिए तथा केंद्र पर दबाव डालना चाहिए। जहां तक भारत की बात है, अगर हिमालय से जुड़ी चिंताओं को जल्द संबोधित नहीं किया गया तो पूरे राष्ट्र को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड व देश के अन्य पहाड़ी राज्यों को एकजुट हो जाना चाहिए। उनके हित साझे हैं, तो प्रयास भी साझे ही होने चाहिएं। दुष्यंत की यह पंक्तियां याद आ रही हैं :

हो गयी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए
आग तेरे सीने में जले
या कि मेरे सीने में
आग जलनी चाहिए
हंगामा खड़ा करना मेरी फितरत नहीं
अपनी आदत है तस्वीर बदलनी चाहिए।

क्रूड ऑयल के लगातार गिर रहे दाम, भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर क्या होगा असर?

परिवहन विशेष न्यूज

Crude Oil Downfall Impact कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। इसकी बड़ी वजह अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के सुस्त पड़ने की आशंका है। क्रूड ऑयल की कीमतें तीन साल के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। आइए समझते हैं कि क्रूड में गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर क्या असर होगा। साथ ही ऑयल कंपनियों के शेयरों में गिरावट क्यों आ रही है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) का भाव लगातार गिर रहा है। अगर ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स की बात करें, तो यह दिसंबर 2021 के बाद पहली बार 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे फिसल गया है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट (Falling crude oil prices) के बावजूद सरकारी ऑयल कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट देखी जा रही है। ONGC के शेयरों में 2.94 फीसदी, IOC में 3.11 फीसदी और BPCL ने 1.49 फीसदी का गोता लगाया है।

आइए जानते हैं कि क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है और इसका भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही, क्रूड में गिरावट के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट क्यों देखी जा रही है।

क्रूड ऑयल में गिरावट क्यों?

क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और चीन (US China economic slowdown) हैं। केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया का कहना है कि चीन में औद्योगिक मंदी के चलते क्रूड ऑयल की डिमांड घटने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया है कि अगर राष्ट्रपति बनते हैं, तो ईरान के तेल उत्पादन की लिमिट घटा देंगे, ताकि वह आमदनी कम हो और वह आतंकवाद की फंडिंग न कर पाए।

नितिन केडिया का कहना है कि शुरुआत में ट्रंप की जीत की संभावनाएं काफी मजबूत थीं, ऐसे में लग रहा था कि ईरान का तेल उत्पादन घटेगा और सप्लाई के मोर्चे पर चुनौतियां पैदा होंगी। लेकिन, अब ट्रंप को कमला हैरिस से काफी तगड़ी टक्कर मिल रही है और उनकी जीत की उम्मीद भी जताई जाने लगी है। इस सूरत में ईरान के तेल उत्पादन पर ज्यादा सख्ती की गुंजाइश नहीं है। इसके चलते भी क्रूड के दाम लगातार गिर रहे हैं।

शेयर मार्केट पर क्या होगा असर?

अगर ओवरऑल देखा जाए, तो कच्चे तेल का दाम घटना (Oil price decline effects) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा है। हमारे आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल का बिल चुकाने में चला जाता है। ऐसे में क्रूड प्राइस घटने से सरकार को राजकोषीय घाटा नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। इससे महंगाई भी नियंत्रित रहती है। अगर सरकार सस्ते क्रूड का फायदा पेट्रोल-डीजल के दाम घटाकर देती है, तो इससे कई कंपनियों को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी कामकाजी लागत कम होगी।

हालांकि, क्रूड प्राइस कम होने से भी ONGC, IOC और BPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया का कहना है कि इन कंपनियों का फिनिश्ड प्रोडक्ट क्रूड है। अगर क्रूड का दाम 75 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आता है, तो माना जाता है कि इन कंपनियों की अर्निंग पर शेयर (EPS) कम हो सकती है। हालांकि, क्रूड का दाम 75 डॉलर से ऊपर जाने की स्थिति में ONGC जैसे शेयरों में दोबारा तेजी देखने को मिल सकती है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल धड़ाम, क्या पेट्रोल-डीजल का भी घटेगा दाम?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के भाव में काफी कमी आई है। अमेरिका में सुस्त आर्थिक आंकड़ों ने क्रूड की कीमतों को नरम किया है। ओपेक प्लस यानी कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों ने अक्टूबर-नवंबर तक प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना को टाले हुए हैं। अगर वे प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला करते हैं तो तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है।

नई दिल्ली। पिछले करीब 6 महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आखिरी दफा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के दाम में दो-दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। अब एक बार पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल, कच्चे तेल (Crude Oil) का दाम लगातार कम हो रहा है। ऐसे में सरकार पेट्रोल-डीजल का रेट कम करके आम जनता को राहत दे सकती है।

कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के भाव में भारी गिरावट आई है। ब्रेंट ऑयल फ्यूचर्स दिसंबर 2021 के बाद पहली बार 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया। दरअसल, मंदी से जुड़ी चिंताओं के चलते क्रूड की डिमांड को लेकर चिंता बढ़ रही है। साथ ही, कच्चे तेल की सप्लाई में तेजी आई है। चीन और अमेरिका के निराशाजनक आर्थिक आंकड़े से वहां तेल की मांग घटने की आशंका है। इन दोनों ही देशों में खपत नहीं बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

दाम घटाने पर विचार कर रही सरकार

बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रूड ऑयल की कीमतें कम होने से तेल कंपनियों का मुनाफा बढ़ा है। अब सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल-डीजल के भाव पर आम लोगों को कुछ राहत देने की स्थिति में आ गई हैं। इस बारे में इंटर-मिनिस्ट्रियल डिस्कशन भी चल रहा है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार तेल की कीमतों में हो रहे बदलाव पर नजर रख रहे हैं। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि सरकार कीमतों में कटौती करेगी या नहीं। कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले वह महंगाई और राजस्व में कमी जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखेगी।

अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े ने किया खेल, क्या अब शेयर बाजार में दिखेगी हलचल?

परिवहन विशेष न्यूज

अमेरिका में मुद्रास्फीति कम हुई है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन स्थिर बनी हुई है। इससे आर्थिक जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व 17-18 सितंबर को होने वाली मीटिंग में ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा। पहले उम्मीद थी कि यह कटौती 0.50 फीसदी तक हो सकती है। इसका शेयर बाजार भी काफी व्यापक असर देखने को मिल सकता है।

नई दिल्ली। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो ने अगस्त 2024 के लिए लेटेस्ट CPI डेटा जारी कर दिया है। इस दौरान अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में कुछ सख्ती दिखाई है। इससे हो सकता है कि फेडरल रिजर्व अगले सप्ताह होने वाली अपनी मीटिंग में ब्याज दर में आधे अंक की कटौती न करे।

अमेरिका में सालाना मुद्रास्फीति दर लगातार पांचवें महीने धीमी होकर अगस्त 2024 में 2.5 फीसदी हो गई। यह फरवरी 2021 के बाद से सबसे कम है। जुलाई में 2.9 फीसदी थी और 2.6 फीसदी के पूर्वानुमान से नीचे थी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल अर्बन कंज्यूमर्स (CPI-U) सीजन के हिसाब से एडजस्ट करके 0.2 फीसदी बढ़ा है।

केडिया फिनकॉर्प के फाउंडर नितिन केडिया का कहना है कि अगस्त 2024 के सीपीआई डेटा से जाहिर होता है कि महंगाई कम हो रही है। खासकर, एनर्जी और फूड सेक्टर में। लेकिन, शेल्टर और सर्विसेज कॉस्ट के चलते कोर इंफ्लेशन अभी भी स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति के नरम पड़ने का असर डॉलर और फेडरल रिजर्व के रेट कट पर भी दिख सकता है।

जुलाई में अमेरिकी CPI घटकर 2.9 फीसदी हो गई और बेरोजगारी स्थिर रही। यह पिछले महीने 4.3 फीसदी के मुकाबले 4.2 फीसदी रही। इससे आर्थिक जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व 17-18 सितंबर को होने वाली मीटिंग में ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा। पहले उम्मीद थी कि यह कटौती 0.50 फीसदी तक हो सकती है।

मुद्रास्फीति के आंकड़े से अमेरिकी शेयर बाजार भी निराश दिया। अमेरिका के सभी प्रमुख सूचंकाकों में शुरुआती कारोबार के दौरान गिरावट दिखी। इनमें डॉव जोन्स, एसएंडपी 500 और NASDAQ 100 शामिल हैं। इस गिरावट का असर गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट पर भी दिख सकता है।

सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी, चांदी की भी बढ़ी चमक

परिवहन विशेष न्यूज

सोने की कीमतों में तेजी का दौर लगातार जारी है। पिछले दो दिनों में सोने का भाव 1000 रुपये से अधिक बढ़ चुका है। चांदी की कीमत भी बुधवार को 500 रुपये बढ़कर 85000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में चांदी 84500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण सोने में तेजी आई।

नई दिल्ली। सोने के दाम (Gold Prices) में लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई। स्थानीय आभूषण विक्रेताओं ने सोने की खरीद बढ़ाई और वैश्विक बाजारों से सोने को बढ़ावा देने संकेत मिले हैं। इससे बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 500 रुपये बढ़कर 74,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मंगलवार को यह 74,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। पिछले दो दिनों में सोने की कीमतों में 1,000 रुपये से अधिक की तेजी आई है।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, चांदी की कीमत भी बुधवार को 500 रुपये बढ़कर 85,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले सत्र में चांदी 84,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस बीच, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 500 रुपये बढ़कर 74,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो पहले 73,750 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

व्यापारियों ने कहा कि स्थानीय आभूषण विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की ओर से खरीदारी बढ़ने से बाजार में सकारात्मक माहौल रहा, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स सोना 0.31 प्रतिशत बढ़कर 2,550.90 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के कमोडिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा,

₹अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण बुधवार को सोने की कीमतों में तेजी आई।₹ साथ ही, शेयर बाजार में बिकवाली और जोखिम से बचने की भावना ने सोने जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्तियों में निवेश बढ़ाया है। इससे भी सोने की कीमतों को समर्थन मिला

आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के कमोडिटीज एंड करेंसीज के एवीपी मनीष शर्मा ने कहा, ₹व्यापारी अब अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट के आधार पर निवेश का फैसला लेंगे, जिससे पता चलेगा कि 18-19 सितंबर को निर्धारित अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में कितनी कटौती होगी।'

पीएलआई स्कीम का दम: एपल ने भारत में तोड़े सारे रिकॉर्ड, पांच अरब डॉलर के आईफ़ोन का किया निर्यात

भारत से आईफोन का निर्यात 2022-23 में 6.27 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 12.1 अरब डॉलर हो गया। कुल मिलाकर कंपनी का भारतीय परिचालन पिछले वित्त वर्ष में 23.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत में कंपनी के राजस्व में 2024 में 18 प्रतिशत (साल-दर-साल) वृद्धि की संभावना है। नई आइफोन 16 सीरीज कंपनी को देश में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगी।

नई दिल्ली। मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल से अगस्त के दौरान एपल ने भारत से पांच अरब डॉलर के आईफोन निर्यात किए। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 50 प्रतिशत ज्यादा है। उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, देश में आईफोन प्रो और आईफोन प्रो मैक्स का उत्पादन शुरू होने के साथ त्योहारी तिमाही और आने वाले महीनों में आईफोन निर्यात का आंकड़ा और बढ़ेगा। नई आईफोन 16 सीरीज देश में 20 सितंबर से आकर्षक फाइनेंसिंग विकल्पों और अन्य ऑफर के साथ उपलब्ध होगी।

केंद्रीय रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, एपल के नवीनतम आईफोन 16 का उत्पादन भारत स्थित मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जा रहा है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'मेक इन इंडिया' पहल अब दुनिया के लिए प्रतिष्ठित उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा दे रही है।" सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) योजना की बदौलत हर महीने आईफोन का निर्यात एक अरब डॉलर तक पहुंच रहा है।

भारत से आईफोन का निर्यात 2022-23 में 6.27 अरब डालर से बढ़कर 2023-24 में 12.1 अरब डॉलर हो गया। कुल मिलाकर, कंपनी का भारतीय परिचालन पिछले वित्त वर्ष में 23.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत में कंपनी के राजस्व में 2024 में 18 प्रतिशत (साल-दर-साल) वृद्धि की संभावना है और नई आईफोन 16 सीरीज कंपनी को देश में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेगी। इतना ही नहीं इसके निर्यात को बढ़ाने का भी काम करेगी।

ग्रे मार्केट में कैसे होता है कारोबार? कितना सटीक होता है इसका अनुमान?

स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ग्रे मार्केट और ग्रे मार्केट प्रीमियम का जिक्र भी होता है। बाजार में आईपीओ लिस्टिंग से पहले निवेशकों की नजर आईपीओ के जीएमपी पर रहती है।आईपीओ में निवेशकों का फोकस Bajaj Housing Finance IPO पर है। इस आईपीओ का जीएमपी भी आ गया है। आइए इस आर्टिकल में जीएमपी और बजाज फाइनेंस आईपीओ के जीएमपी के बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले कंपनी निवेशकों के लिए अपना आईपीओ लॉन्च करती है। बाजार में अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ (Bajaj Housing Finance) को लेकर काफी क्रेज है। आज बजाज फाइनेंस के आईपीओ (Bajaj Housing Finance IPO) में बोली लगाने का आखिरी दिन है। बता दें कि पिछले दो कारोबारी सत्र में कंपनी के आईपीओ पर निवेशकों का काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है।

ऐसे में अब ग्रे मार्केट प्रीमियम (Grey Market Premium) पर भी कंपनी के शेयर की लिस्टिंग को लेकर चर्चा हो रही है। जी हां, जब भी आईपीओ (IPO) की चर्चा होती है तब जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी जिक्र होता है। ऐसे में बजाज हाउसिंग फाइनेंस के जीएमपी (Bajaj Finance GMP) के बारे में जान लेने से पहले हमें आईपीओ और जीएमपी (GMP) के कनेक्शन को समझ लेना चाहिए।

क्या होता है ग्रे मार्केट? (What is Grey Market)

ग्रे मार्केट (Grey Market) एक तरह का शेयर बाजार ही है। हालांकि यह मुख्य स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) से काफी अलग है। इसमें शेय की लिस्टिंग से पहले उनकी ट्रेडिंग की जाती है। ग्रे मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है वह व्यक्तिगत होता है यानी यह बाजार के नियमों से बाहर है। लेकिन, इसकी ट्रेडिंग को भी अवैध नहीं माना जाता है।

ग्रे मार्केट का पूरा कारोबार भरोसे पर चलता है। किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग कैसी होगी? इसका अंदाजा ग्रे मार्केट में आईपीओ की परफॉर्मेंस (IPO Performance) पर लगाया जाता है। ग्रे मार्केट में आईपीओ कितने भाव पर मिल रहा है और उसके कितने खरीदार है, इन सभी के बाद कंपनी अंदाजा लगाती है कि आईपीओ की लिस्टिंग कैसी होगी।

ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है? (What is Grey Market Premium)

ग्रे मार्केट की जब चर्चा होती है तो उसके प्रीमियम यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम (Grey Market Premium) का भी जिक्र होता है। दरअल बाजार में कई ऐसे शेयर होते हैं जिनके बारे में उम्मीद जताई जाती है कि वह प्रीमियम के साथ लिस्ट होंगे। ऐसे में शेयर की लिस्टिंग से पहले ही ग्रे मार्केट आईपीओ प्राइस से ज्यादा पेमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। आईपीओ से ज्यादा जितनी रकम दी जाती है उसे ग्रे मार्केट प्रीमियम कहते हैं।

इसे ऐसे समझें कि अगर किसी आईपीओ का प्राइस इश्यू 500 रुपये है लेकिन ग्रे मार्केट में वह 520 रुपये पर ट्रेड कर रहा है तो जो अतिरिक्त 20 रुपये है वह ग्रे मार्केट प्रीमियम है।

कितना सही है ग्रे मार्केट प्रीमियम?

ग्रे मार्केट कभी भी शेयर की लिस्टिंग को लेकर सटीक जानकारी नहीं देता है। जीएमपी से हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर की लिस्टिंग कैसे होगी। ऐसे में जीएमपी पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप किसी आईपीओ में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको केवल जीएमपी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप पहले खुद से रिसर्च करें या फिर किसी विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार या मार्केट एक्सपर्ट से सलाह लें और फिर निवेश करें।

बजाज हाउसिंग फाइनेंस जीएमपी (Bajaj Housing Finance GMP)

ग्रे मार्केट में Bajaj Housing Finance को लेकर कमाई का संकेत मिल रहा है। अभी ग्रे मार्केट में जीएमपी 65 रुपये है। इसका मतलब है कि अगर जीएमपी के हिसाब से आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो स्टॉक प्राइस 135 रुपये प्रति शेयर हो सकता है। इसका मतलब है कि आईपीओ का लिस्ट होते ही निवेशकों को 92 फीसदी से ज्यादा का मुनाफा होगा।

गणेशोत्सव राष्ट्रीयता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतिक : फिल्म निर्माता सावन चौहान

समस्त देशवासियों को श्रीगणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। भारत पर्व-उत्सवों का देश है, और गणेश चतुर्थी उन्हीं विशेष उत्सव में से एक है। गणेशोत्सव को 10 दिनों तक बड़े धूम-धाम और उत्साह से मनाया जाता है। इस त्योहार को गणेशोत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्मदिन के इस उत्सव को उनके भक्त बहुत उत्साह के साथ मना रहें हैं।

गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर फ़ल्मि निर्माता सावन चौहान ने समस्त देशवासियों को श्रीगणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हे विघ्नेश्वर, वर देने वाले सभी देवताओं को प्रिय, लम्बोदर, कलाओं से परिपूर्ण, जगत का हित करने वाले, गज के समान मुख वाले और वेद तथा यज्ञ से विभूषित माँ पार्वती के प्रिय पुत्र, बुद्धि एवं समृद्धि के आराध्य देव भगवान श्री गणेश जी की सभी पर कृपा हो और सभी के जीवन में सदैव उत्साह, आनंद, उल्लास का वास हो। हर घर-आंगन में शुभता और मांगल्य की वर्षा हो, यही हमारी कामना है। गणेश जी सभी को बुद्धि एवं समृद्धि प्रदान करें, सभी के दुखों का नाश करें और सभी के जीवन में खुशियां बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं कि गणेश जी सभी को सुख, बुद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें और श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। समस्त देशवासियों को पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

श्री चौहान ने आगे कहा, हमारा भारत देश अपनी सांस्कृतिक विशेषता के कारण दुनियां में एक अलग पहचान रखता है। यही सांस्कृतिक विशेषता हमारे देश को श्रेष्ठता प्रदान करती हैं, इस विशेषता के दर्शन तीज त्यौहार, उत्सव, परंपराओं में होते है। इसी तरह की सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता भारत में दस दिवसीय गणेश उत्सव में नज़र आती हैं। इसीलिए यह उत्सव किसी विशेष जाति, वर्ग का नहीं होकर राष्ट्रीय उत्सव नजर आता है। गणेश उत्सव ने देश की राष्ट्रीय चेतना जगाने और सामाजिक समरसता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पवित्र गणेशोत्सव पर्व राष्ट्रीयता और हिन्दू एकता की भावना जगाता हैं। इस उत्सव की खास बात यह है की यह समाज के सभी वर्गों में समान उत्साह, उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। छुआछूत भेदभाव और आर्थिक मतभिन्नता के परे इस उत्सव में गजब की सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता के दर्शन होते है। आजाद भारत में भी गणेश उत्सव राष्ट्रीयता, हिन्दू एकता, सांस्कृतिक एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बना हुआ है। गणेश उत्सव सांस्कृतिक रूप से भारतीय जनमानस में हिन्दू एकता स्थापित करने का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है। हमारे पर्व सदैव हिन्दू एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ईमानदार ऑटो चालक की खूब हो रही सराहना, लालच में न डगमगाया मन; पुलिस की मदद से महिला को मिला खोया बैग

गुरुग्राम में एक महिला का बैग ऑटो में छूट गया। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत की। उधर ऑटो चालक ने भी ईमानदारी का परिचय देते हुए महिला के बैग को थाने में जमा करा दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला को उनका बैग लौटा दिया। जानिए आखिर पुलिस ने कैसे ऑटो चालक से संपर्क किया और बैग प्राप्त कर लिया।

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला घर का सामान शिफ्ट करने के दौरान ऑटो में अपना बैग भूल गई। इस संबंध में महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। उधर, ऑटो चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए महिला के बैग को थाने में जमा करा दिया। जिसके बाद पुलिस ने महिला को उनका बैग लौटा दिया। सेक्टर 40 थाना पुलिस के अनुसार, ऑटो चालक मनीरुल जमां ने ईमानदारी का परिचय देते हुए महिला के बैग को थाने में जमा कराया था। वहीं, गुरुग्राम पुलिस और ऑटो चालक की सराहना करते हुए महिला के एक मित्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है।

बैग में थे कई जरूरी सामान

सेक्टर 40 थाना पुलिस ने बताया कि सात सितंबर को एक महिला ने थाने में शिकायत दी कि वह सेक्टर 43 से सेक्टर 45 में घर का सामान शिफ्ट कर रही थीं। इस दौरान ऑटो में उनका एक बैग रह गया था। इस बैग में कई जरूरी दस्तावेज, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और सोने की चेन थी।

ऑटो चालक से ऐसे किया गया संपर्क

थाने में तैनात एएसआई रामबीर ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। ऑटो की नंबर प्लेट से चालक की पहचान करते हुए उससे संपर्क किया गया।

इसके बाद चालक भी सामान से भरा बैग थाने में जमा कर गया। महिला को थाने बुलाकर उनका बैग सौंप दिया गया। इस पर उन्होंने गुरुग्राम पुलिस और ऑटो चालक का धन्यवाद किया।

सांगवा की फुटी नाडी, रामपुरिया का फूटा तालाब तो गुरलां स्थित रणजीत सागर तालाब की चल पड़ी डेढ़ फीट चादर

कारोई नायब तहसीलदार ने पटवारी को दी सूचना फिर भी मौके पर नहीं आई पटवारी।

–सांगवा, बांसड़ा, सुन्दरपुरा में तेज बरसात से रामपुरिया तालाब भी लबालब होकर दो जगहों से फुट गया तो इधर गुरलां से मोमी व गाडरमाला का रास्ता भी हुआ बन्द।

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा कारोई क्षेत्र के गुरलाँ व आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को हुई तेज बरसात के बाद सांगवा ग्राम पंचायत स्थित नाडी में गल्ला लगने व इसके बाद फुटने के कारण पानी का बहाव तेज हो गया वही छोटी नाडी के भी ओवरफ्लो होकर बहने से एवं बांसड़ा क्षेत्र में भी तेज बारिश होने के चलते रामपुरिया ग्राम का तालाब भी ओवरफ्लो हो गया। एकाएक तेज गति से आये पानी के कारण रामपुरिया तालाब दो जगहों से फुट गया जिसके चलते गुरलाँ के रणजीत सागर तालाब में पानी की आवक बढ़ गई। नतीजन पहले से चल रही चादर को और पंख लग गए। जिससे वह डेढ़ फीट तक चल पड़ी।

इधर गुरलां के ग्रामीणों ने बताया कि आज से ठीक 8 वर्ष पूर्व 2016 में इसी तरह रणजीत सागर तालाब की रपट करीबन 1 महीने तक चली थी और आज फिर से एक बार इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते रणजीत सागर तालाब पर डेढ़ फीट की चादर चल पड़ी हैं।

मंगलवार देर रात तक चली रामपुरिया तालाब फूटने की अफवाह, मगर बुधवार दोपहर आखिर फुट ही गया।*

मंगलवार को कारोई व आसपास के क्षेत्र में हुई अच्छी बरसात के बाद हुई पानी की आवक से क्षेत्र में रामपुरिया तालाब के फुटने की मंगलवार देर रात तक अफवाह फैलती रही मगर ये अफवाह बुधवार अल सुबह स्पस्ट हो गई कि ऐसा नहीं हुआ हैं और तालाब में तेज गति से पानी की आवक लगातार जारी हैं। जिसके चलते रणजीत सागर तालाब की डेढ़ फीट चादर चल रही हैं।

इसके साथ ही गुरलाँ के रणजीत सागर तालाब के केचमेन्ट क्षेत्र में सांगवा की नाडी के फुटने से एवं रामपुरिया तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण व बाँसड़ा, सुन्दरपुरा क्षेत्र में तेज बरसात से भी रणजीत सागर तालाब।ओवरफ्लो होकर छलक चुका हैं। जिसके कारण लावड़ो का बाड़ा, मोमी, चाँवन्डेरी, जागदरी, गाडरमाला आदि मार्ग भी बन्द हो गये हैं। वही ग्रामीणों ने बताया कि एक भैंस का बछड़ा भी रणजीत सागर तालाब की रपट से निकल रहे पानी में बह गया था। वही दोपहर करीबन 12 बजे के आसपास सूचना मिली कि रामपुरिया तालाब दो जगहों से फुट गया हैं। सूचना मिलने पर भीलवाड़ा तहसीलदार दिनेश यादव व कारोई नायब तहसीलदार राकेश कुमार भारद्वाज भी गुरलां स्थित रणजीत सागर तालाब और रामपुरिया तालाब के मौके पर पहुँचे। जहां पहुँच उन्होंने वस्तुस्थिति का जायजा लिया और त्वरित कार्यवाही करते हुए फूटे तालाब की दोनों जगहों का पानी रोकने के लिए रेत व सीमेंट के कट्टे डलवाये।

तहसीलदार, नायब तहसीलदार पहुँचे मौके पर, नहीं आई पटवारी।

कारोई क्षेत्र की रामपुरिया ग्राम पंचायत का तालाब के फूटने की सूचना पर भीलवाड़ा तहसीलदार दिनेश यादव तथा कारोई नायब तहसीलदार राकेश कुमार भारद्वाज भी मौके पर रामपुरिया तालाब व गुरलां स्थित रणजीत सागर तालाब पर पहुँचे। दोनों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया। जहां पर रामपुरिया तालाब में दो जगहों से फूटे तालाब का पानी बह रहा था। वही जेसीबी व ट्रेक्टर की सहायता से वहां रेत व सीमेंट के कट्टे आदि डलवाकर पानी को रोकने के प्रयास किए। इस दौरान नायब तहसीलदार राकेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने रामपुरिया पटवारी पूजा कँवर शेखावत को मौके पर पहुँचने की सूचना दी। मगर सूचना देने के बावजूद भी रामपुरिया पटवारी पूजा कंवर शेखावत मौके पर नहीं पहुँची।

न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोपी को किया दोषमुक्त

अधिवक्ता अरविन्द पुष्कर द्वारा मजबूती से रखें गए तर्कों को सुनने के उपरांत अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में रहा असफल

आगरा। जिला एवं सत्र न्यायालय दीवानी कचहरी में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) के विशेष सत्र परीक्षण संख्या-136/2021में आरोपित के अधिवक्ता के द्वारा मजबूती एवं गंभीरता के साथ रखें गए तर्कों को सुनने के उपरांत अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा तथा न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने योग्य मानते हुए अपने एक आदेश में कल आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया।

इस सन्दर्भ में आरोपित के विद्वान अधिवक्ता अरविन्द कुमार पुष्कर ने न्यायालय के आदेशानुसार बताया कि माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट) आगरा ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत न्यायहित में अपने एक आदेश में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरिभान उर्फ हरिशंकर पुत्र अरविन्द, थाना बाह, मु०अ०सं० 173/2021 धारा 366, 376, 506 भा०द०सं०, व धारा 3(2) (V) एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अंतर्गत आरोपी हरिभान को दोषमुक्त कर दिया। श्री पुष्कर ने आगे बताया, इस मुकदमे में हरिभान उर्फ हरिशंकर के विरुद्ध जो आरोप लगाए वो माननीय न्यायालय में युक्ति युक्त संधेय से परे सिद्ध नहीं हुऐ और अभियोजन आरोपों को साबित करने में असफल रहा। इस आधार पर न्यायहित में माननीय न्यायालय ने आरोपित को समस्त आरोपों को खारिज कर मुकदमे में आरोपित को दोषमुक्त कर दिया।

आयुष्मान भारत का बनेगा नया कार्ड, रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी। इससे करीब छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर से करीब 4.5 करोड़ परिवारों के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। पात्र लाभार्थियों को एक नया अलग कार्ड जारी किया जाएगा।

नईदिल्ली। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख रूपये सालाना तक मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना से चार करोड़ परिवार में रहने वाले छह करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा।

आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण

इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण करना होगा। जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि योजना 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को कवर किया जाएगा।

कुल 10 लाख तक का कवर

जिन परिवारों को पहले से आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जा रहा है, उनमें भी 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग अलग से पांच लाख रुपये सालाना इलाज करा सकेंगे। यानी ऐसे परिवारों को जिन्हें पहले से आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, उन्हें अब कुल 10 लाख तक का कवर होगा। यदि किसी परिवार में दो बुजुर्ग हैं, तो दोनों के बीच संयुक्त रूप से यह सुविधा होगी।

तहत मुफ्त इलाज की सुविधा

अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहले से केंद्र, राज्य या किसी अन्य सरकारी विभाग की योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा पाने वाले बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान भारत के तहत इलाज का कवर पाने का विकल्प खुला होगा। ऐसे बुजुर्ग यदि चाहें तो किसी इलाज के पुराने कवर को छोड़कर आयुष्मान योजना से इलाज की सुविधा हासिल कर सकते हैं।

3437 करोड़ रुपये आवंटित

ईएसआइसी के तहत इलाज के लिए कवर किये जाने वाले बुजुर्ग भी आयुष्मान भारत के तहत कवर किये जा सकेंगे। यही नहीं, जिन बुजुर्गों ने निजी बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वैष्णव ने कहा कि फिलहाल इस योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, लेकिन मांग बढ़ने पर इसमें बढ़ोतरी का विकल्प खुला रहेगा।

सालाना मुफ्त और कैशलेश इलाज

ध्यान देने की बात है कि मोदी सरकार ने 2017 में देश भर के 10.74 करोड़ गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच लाख रुपये सालाना मुफ्त और कैशलेश इलाज के लिए कवर किया गया था। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में इस योजना का लाभ 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को देने का वादा किया था। कैबिनेट ने इस वायदे को पूरा कर दिया है।

अनमोल रिश्तें

आपस में रिश्ते एक स्नेह की जंजीर है।
यह मानो एक डोर है यह एक अंजीर है।

ना तुम साथ रहकर निभा पाए।
ना तुम अलग रहकर जोड़ पाए।

गुजर रही है जिंदगी कब करोगे कोशिश?
क्या? कभी नहीं नमाओगे अपना शीश?

संभलने को तो अभी-भी शेष है।
जान लो तुम अभी-भी विशेष है।

सर झुका कर हाथ ही तो आगे बढ़ाना है।
बस सामने रिश्तों का अनमोल खज़ाना है।

संजय एम तराणेकर

साइबर क्राइम के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन

साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए अभियान में अभिनेता अमिताभ बच्चन शामिल हो गए हैं। अमिताभ बच्चन ने कहा कि साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है जो भारत के साथ ही विश्व के लिए भी चिंता का विषय है। बता दें कि साइबर अपराध को रोकने के लिए आइ4सी लगातार काम कर रहा है।

नई दिल्ली। साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किए गए अभियान में अभिनेता अमिताभ बच्चन शामिल हो गए हैं। आइ4सी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में अमिताभ बच्चन ने कहा कि साइबर अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है जो भारत के साथ ही विश्व के लिए भी चिंता का विषय है।

आगे कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए आइ4सी लगातार काम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के अनुरोध पर मैं भी इस अभियान में शामिल हुआ हूं। मेरी अपेक्षा है कि हम सभी लोग इस समस्या से लड़ने के लिए एकजुट होंगे। हमारी सतर्कता और सावधानी, हमें साइबर अपराधियों से बचा सकती है। मैं आपको समय-समय पर याद दिलाता रहूंगा।

अमित शाह ने जताया आभार

इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की शाखा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइ4सी) ने शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमिताभ के इस अभियान में शामिल होने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी के दृष्टिकोण को अपनाते हुए गृह मंत्रालय देश में एक सुरक्षित 'साइबरस्पेस' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

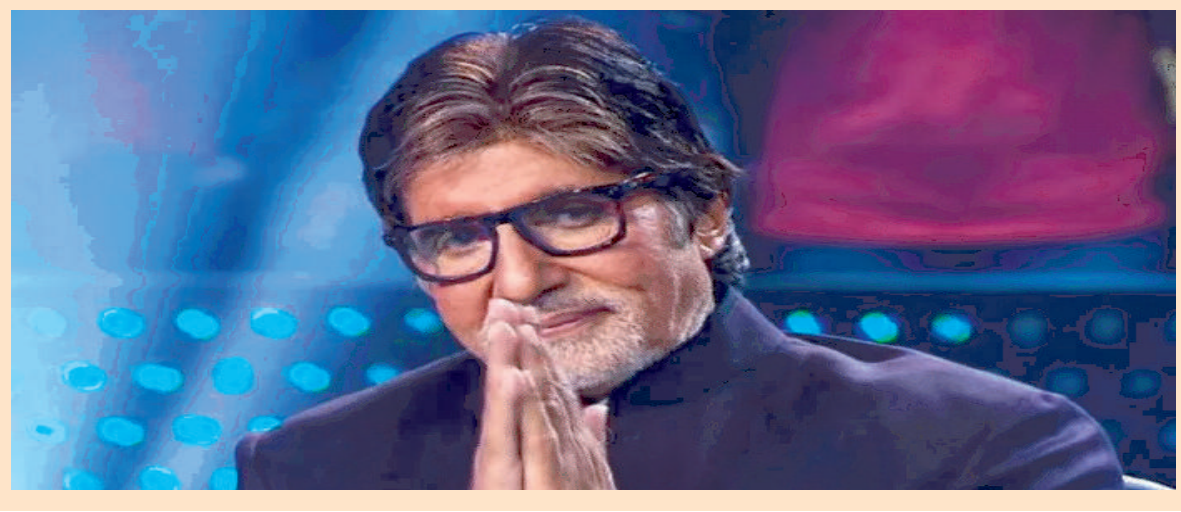

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023